

# NOW NOIDA

वॉल्यूम 1 | अंक 5 | May 2024

## अपडेट

Title-Code: UPHIN51287

कैराना को कौन पसंद है?

जब हिंदी फिल्मों में  
गूँजे संविधान को  
बर्चाने के डॉयलाग

स्क्रैप माफिया के काले  
साम्राज्य का "द एंड" ?







**STARTING  
FROM  
₹ 125**

# Baby Bed Protector

Perfect Baby Bed Sheet Waterproof  
for Ultimate Comfort

**BUY NOW**

✉ [sales@madebyindia.com](mailto:sales@madebyindia.com)

☎ 07011412854

🌐 [www.madebyindia.com](http://www.madebyindia.com)



### सत्य से साक्षात्कार

संपादक मंडल

संपादक :	संदीप ओझा
सहयोगी संपादक :	निर्मल गौड़
नोएडा ब्यूरो चीफ :	यूनस आलम
वरिष्ठ संवाददाता :	ओम प्रकाश सिंह
संवाददाता :	साजिद अली
कला और सयंजोन :	अनिरुद्ध शी, गुलशन कुमार
कानूनी सलाहकार	मौ. शाहिद, एडवोकेट
प्रबंध निदेशक :	संदीप ओझा
निदेशक एवं प्रकाशक :	<b>MBI DIGITAL PVT LTD</b>
पंजीकृत कार्यालय :	प्लॉट नंबर 99 इकोटेक 3 उद्योग केंद्र 2 ग्रेटर नोएडा 201306
	<b>MBI DIGITAL PVT LTD</b>
	प्लॉट नंबर-99, इकोटेक थर्ड, उद्योग केंद्र-2 ग्रेटर नोएडा-201306
मुद्रक एवं प्रकाशक :	दूरभाष- +91 120-4553364 infonownoida@gmail.com

एमबीआई डिजिटल प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सन्दीप कुमार ओझा द्वारा प्लॉट नंबर-99, इकोटेक-थर्ड, उद्योग केंद्र-दो, ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) से प्रकाशित व चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क प्रा. लि. नोएडा, सी-40, सेक्टर-8 नोएडा से मुद्रिता। संपादक सन्दीप कुमार ओझा (TITLE-CODE: UPHIN51287)

झूठी शान	03
सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला भारत चौथा देश	04
विश्व के सबसे लंबे ट्रेन रूट्स	05
चरमराती यातायात व्यवस्था: कैसे होगा समाधान?	06



कवर स्टोरी

## मंगलसूत्र और संविधान पर बिछी बिसात

पृष्ठ - 20

इसलिए केंद्र की राजनीति में यूपी की धमक	09
चुनावी खर्च	12
कैराना को कौन पसंद है?	16
बड़े चेहरे	24
जब हिंदी फिल्मों में गूंजे संविधान को बचाने के डॉयलाग	28
मतदान प्रतिशत गिरने का मतलब क्या?	30
दोनों चरणों में कम पड़े वोट	34

विश्व में 28 करोड़ लोगों को पड़े रोटी के लाले	39
स्क्रेप माफिया के काले साम्राज्य का "द एंड" ?	40
UPSC क्लैक करने का मूल मंत्र	42



"मृदा प्रदूषण"	44
लोकसभा महापर्व	48



चुनाव के समय गोल्ट और कैश लेकर चलने के नियम	36
---	----





# संपादकीय



## संकल्प या न्याय

चुनाव जीतने के लिए हर राजनीतिक दल अपने पैतरे अजमाता ही है। लोकसभा चुनाव के साथ ही लोकलुभावन दावों की पोटली भी खोली जा रही है। चाहे बीजेपी का “संकल्प पत्र” हो या कांग्रेस का “न्याय पत्र”। कांग्रेस ने इस बार “न्याय” को थीम बना कर घोषणा पत्र जारी किया है, तो बीजेपी ने “संकल्प पत्र”। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव में करीबी मुकाबला होगा, जिसमें विपक्ष को इस बार विजयी प्राप्त होगी। इधर बीजेपी ने 400 पार के एजेंडे को सेट किया है।

### एक नजर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर

कांग्रेस के 45 पेज के घोषणा पत्र में 25 गारंटी के आस-पास घूमता है, जिसमें सरकारी रिक्त पदों पर भर्तियां, आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू करना, सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को खत्म करना आदि शामिल है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, गरीब भारतीय परिवार को प्रत्येक वर्ष एक लाख प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ भी कांग्रेस के न्याय पत्र का हिस्सा है।

### बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या?

भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए “संकल्प पत्र” को जारी किया। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी (एनडीए) की सरकार है। बीजेपी का दावा है कि उन्होंने इस दो कार्यकाल के दौरान घोषणा पत्र में जारी हर पहलु को गारंटी के साथ लागू किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बार देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है “समान नागरिकता

संहिता”, जिसे बीजेपी राष्ट्रहित में बता रही है। इसके अलावा घोषणा पत्र में “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पहल को लागू करने, आम मतदाता की सूची तैयार करने, ट्रेन यात्रा के लिए प्रतीक्षा सूची को खत्म करने, 5जी नेटवर्क के विस्तार और दुनिया भर में रामायण त्योहारों का आयोजन की बात की गई है।

लोकसभा चुनाव में पहले दो चरणों के चुनाव संपन्न हो गये हैं। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि दूसरे फेज़ में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गये। कुल मिलाकर अब तक दो चरणों में 190 सीटों पर मतदान संपन्न हो गये हैं। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों के लिए होने वाले मतदान तक लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे रंग में आ जाने के आसार हैं। इस बार चुनाव में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की अहम भूमिका होने जा रही है। खासकर कांग्रेस के प्रत्याशी अपने न्याय पत्र को लेकर लोगों के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। जबकि बीजेपी पिछले अपने 10 सालों के काम और आगे के विजन को लेकर लोगों के बीच है। हालांकि ये 4 जून को तय हो जाएगा कि किसके घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकार किया।

संदीप ओझा  
संपादक





# झूठी शान



**अजय पाल नागर**  
लेखक एवं शिक्षाविद

आधुनिकता सर चढ़कर नाच रही है, युवा पीढ़ी नशा करके डी.जे. पर झूम रही है। झूठी शान दिखाने के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहे हैं और डी.जे. बुजुर्गों व नवजात बच्चों की जान को खतरा बन रहा है।

जी हां ! दिल्ली NCR क्षेत्र में कोई शादी हो और राजा महाराजाओं जैसी चकाचौंध न हो ऐसा कैसे हो सकता है ? शादियों के सीजन में दिल्ली NCR क्षेत्र में घर से निकलना मतलब मुसीबत में पड़ना। आधा घंटे का सफर दो से तीन घंटों में पूरा करना पड़ता है। विशेष रूप से नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम तो समझिये पूरा ठहर सा जाता है। सभी फार्म हाउस शादियों के लिए बुक हो जाते हैं और ऐसी लाखों गाड़ियां जो घर पर खड़ी रहती थीं, वह भी सड़कों पर उतर जाती हैं। शादियों में समय से पहुंचा जाए या न पहुंचा जाए लेकिन जाना गाड़ियों से ही होता है। स्टेटस का सवाल जो है। यारों और रिश्तेदारों को भी तो दिखाना होता है कि अब हम भी तो गाड़ी वाले हैं तो इसमें गलत भी कुछ नहीं है। बस सड़क ही तो जाम होती है। देर रात तक हार थककर घर पहुंच ही जाते हैं। यार -रिश्तेदारों में भौंकाल तो बन ही जाता है।

## जमकर होती है खाने की बर्बादी

अब बात करते हैं शादी की व्यवस्था की। सभी शादियों में आमतौर पर दो से तीन हजार लोगों का खाना बनवाया जाता है। क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों को सभी निमंत्रण दिया जाता है और उन्हें सभी शादियों में जाना भी पड़ता है। कुछ मजबूरी में और कुछ शौक में और कुछ भावी महत्वाकांक्षाओं को लेकर पहुंचते हैं। चर्चा में गणमान्य लोगों को यह भी बताना होता है कि आज पच्चीस शादियों का निमंत्रण है या बीस का निमंत्रण है। अब सभी में पहुंचना है तो रात की शादी में दिन से आना-जाना शुरू हो जाता है। आधी-अधूरी तैयारियों के बीच गणमान्य लोग शादियों में पहुंचते हैं तब तक टेंट ही लग रहा होता है। खाना तो दूर की बात है और खाना केवल एक ही शादी

में बामुश्किल खाया जाता है। बाकी शादियों में उनके हिस्से का बना खाना बच जाता है।

## सिर्फ दाल-रोटी खाने की मचती है होड़, बाकी पकवान शो पीस

खाने में पांच -छः प्रकार की सब्जियां, पांच-छः प्रकार की मिठाईयां और न जाने कितने ही व्यंजन होते हैं। लेकिन खाने वालों की भीड़ दाल रोटी पर मिलती है। जब दाल रोटी ही खानी है तो फिर अनगिनत व्यंजन किस लिए बनवाते हैं ? केवल दिखावे के लिए। जिन्हें खाना तो दूर की बात है देखा भी नहीं जाता। यह खाने की बर्बादी के साथ-साथ धन की भी बर्बादी है। सभी लोग तो धन कुबेर हैं नहीं, कुछ तो पुश्तैनी जमीन बेचकर और कुछ कर्ज लेकर यह शान दिखाते हैं और एक दिन का राजा-महाराजा बन जाते हैं।

## सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे डीजे वाले बाबू

अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो म्यूजिक के नाम पर जो कानफोड़ और जानलेवा संगीत 4-5 डीजेपर सुनने को मिल रहा है। उससे उन चंद नशा खोर युवाओं को तो क्षणिक आनंद आ रहा है जो अभी स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति अनजान हैं और अज्ञानतावश स्वयं व बुजुर्गों और बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में डीजे की ध्वनि को 45-55 डेसीबल निर्धारित किया है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां इसलिए उड़ायी जाती हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जो कानफोड़ व जानलेवा डीजे की ध्वनि का मापन कर सके। जिसका लाभ डीजे संचालक और कानफोड़ व जानलेवा संगीत का आनंद लेने वाले युवा उठा रहे हैं।

अब यदि आप जागरूक हैं और अपना व अपने समाज का हित चाहते हैं तो ऐसी जानलेवा सामाजिक बुराई का परित्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। ताकि हम सभी स्वस्थ व सुरक्षित रह सकें।



# सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला भारत चौथा देश



दुनियाभर में सैन्य खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी सामरिक जरूरतों को देखते हुए भारत भी इसमें कोई कोताही नहीं कर रहा है। सेना व हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक के अनुसार, 2023 में भारत का सैन्य खर्च 8,360 करोड़ डालर था। शीर्ष तीन देशों में अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं। स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की अप्रैल में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत का सैन्य खर्च 2022 की तुलना में 4.2 प्रतिशत और 2014 की तुलना में 44 प्रतिशत बढ़ गया। भारत के सैन्य खर्च में वृद्धि मुख्य रूप से कर्मियों की संख्या और संचालन लागत का परिणाम है। इन मदों में कुल सैन्य बजट का लगभग 80 प्रतिशत खर्च किया गया।

सिपरी के अनुसार, भारत का सैन्य खर्च चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता को मजबूत करने की सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। इसकी तुलना में सैन्य खरीद के लिए पूंजी परिव्यय बजट के लगभग 22 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत स्थिर रहा। परिव्यय का कुल 75 प्रतिशत घरेलू स्तर पर बनाए गए उपकरणों पर खर्च किया गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। घरेलू खरीद की ओर निरंतर बढ़ते कदम हथियारों के विकास और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के भारत के लक्ष्य को दर्शाता है। 2023 में लगातार नौवें वर्ष वैश्विक सैन्य खर्च में बढ़ोतरी हुई। वैश्विक स्तर पर कुल सैन्य

खर्च 2,44,300 करोड़ डालर तक पहुंच गया। वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से यूक्रेन में चल रहे युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

रिपोर्ट कहती है-विश्व सैन्य व्यय 2023 में लगातार नौवें वर्ष बढ़कर कुल 2443 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2023 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि 2009 के बाद से साल-दर-साल सबसे तेज वृद्धि थी और इसने वैश्विक खर्च को सिपरी द्वारा अब तक दर्ज उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। विश्व सैन्य बोझ 2023 में बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गया, जिसे वैश्विक GDP में सैन्य खर्च की हिस्सेदारी को प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

इसके अलावा रिपोर्ट कहती है कि सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में औसत सैन्य व्यय 2023 में 0.4 प्रतिशत अंक बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गया। प्रति व्यक्ति विश्व सैन्य खर्च 1990 के बाद से सबसे अधिक 306 डॉलर था। भारत 2023 में 83.6 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ दुनियाभर में सैन्य खर्च के मामले में चौथे स्थान पर था। भारतीयों द्वारा खर्च 2022 से 4.2 प्रतिशत और 2014 से 44 प्रतिशत बढ़ गया है। इसमें कहा गया कि भारत के सैन्य खर्च में वृद्धि 'मुख्य रूप से बढ़ती कार्मिक और परिचालन लागत का परिणाम थी' जो 2023 में कुल सैन्य बजट का लगभग 80 प्रतिशत थी।



# विश्व के सबसे लंबे ट्रेन रूट्स

भारत में रहने वाले करीब 99 फीसद लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। क्योंकि ट्रेन ही है जो कम पैसों में लंबी दूरी तय कराती है। सबसे अधिक भारत की ट्रेनों में भीड़ होती है। वहीं, सबसे तेज गति से ट्रेन चीन में चलती है। शंघाई मैगलेव नाम की ट्रेन 460 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे रूट हैं, जिन पर चलने में ऐसी ट्रेनों के भी पसीना छूटना तय है। विश्व में एक रूट तो इतना लंबा है कि वह एक महासागर से शुरू होकर दूसरे महासागर तक जाता है। दुनिया के पांच सबसे लंबे रेल रूट्स में भारत का भी एक रूट शामिल है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देश में सबसे लंबा रेल रूट है। देश की राजधानी मॉस्को को पूर्वी शहर व्लाडीवोस्तोक से जोड़ता है। 9,259 किमी लंबे इस रूट पर यात्रा पूरी करने में आम ट्रेन को सात दिन का समय लगता है। अगर भारत की वंदे भारत को 160 किमी की पूरी रफ्तार से चलाया जाए तो इस रूट पर यात्रा करने में करीब 58 घंटे लगेंगे। इसी तरह 460 किमी की रफ्तार से चलने वाली चीन की मैगलेव ट्रेन को भी यह यात्रा पूरी करने में पूरे 20 घंटे लगेंगे।

दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रूट कनाडा में है। यह रूट टोरंटो को वैंकूवर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 4,466 किमी है। आधिकारिक रूप से इस यात्रा को पूरा होने में चार दिन का समय लगता है। इस ट्रेन से प्रकृति के शानदार नजारे दिखते हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन का न्यूनतम किराया 529 डॉलर है। इस रूट पर बुलेट ट्रेन को 11 घंटे से अधिक समय लगेगा जबकि वंदे भारत फुल स्पीड से एक दिन में यह सफर तय कर सकती है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल रूट चीन में है। राजधानी शंघाई को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता है। इसकी लंबाई 4,373 किमी है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन यात्रा पूरी करने में ट्रेन 46 घंटे 44 मिनट यानी करीब दो दिन का समय लेती है। यह शंघाई रेलवे स्टेशन से रात 08.02 बजे छूटती है और दो दिन बाद शाम 06.46 बजे ल्हासा पहुंचती है। इस सफर को पूरा करने में भी बुलेट को आधा दिन लग जाएगा।

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का रेल रूट है। सिडनी से पर्थ को जोड़ने वाला यह रूट 4,352 किमी लंबा है। इस रूट पर इंडियन पैसिफिक ट्रेन चलती है, जो चार दिन में यात्रा पूरी करती है। यह हिंद महासागर के तट से चलती है और प्रशांत महासागर के तट पर पहुंचती है। इस यात्रा के दौरान कुदरत के कई करिश्मे भी दिखते हैं। इस दौरान ट्रेन दुनिया के सबसे लंबे स्ट्रेट स्ट्रेच से गुजरती है। 478 किमी लंबा यह स्ट्रेच दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है जिसे The Nullarbor कहते हैं। वंदे भारत को फुल स्पीड से सफर पूरा करने में पूरा एक दिन लगेगा।

भारत की सबसे लंबी रेल लाइन असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है। यह दुनिया का पांचवां सबसे लंबा रेल रूट है। इसकी लंबाई 4,237 किमी है। इस रूट पर चलने वाली विवेक एक्सप्रेस को अपनी यात्रा पूरी करने में 72 घंटे का समय लगता है। अगर इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस को पूरी स्पीड के साथ चलाया जाए तो उसे इस दूरी को तय करने में 26 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह मैगलेव ट्रेन को यह दूरी तय करने में करीब 10 घंटे का समय लगेगा।



# चरमराती यातायात व्यवस्था: कैसे होगा समाधान?



दिनकर पांडेय  
समाजसेवी

अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सड़कों से गुजरेंगे तो यातायात में घंटों फंसना पड़ सकता है। अक्सर कार्यालय जाते समय, या वापस लौटते समय लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। कुछ सड़कों को छोड़ दें, जैसे एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड इत्यादि तो अधिकतर हालात ऐसे ही हैं। अब सवाल उठता है कि जनता इतनी परेशान है तो इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा? क्या प्रशासन, यातायात पुलिस या जनप्रतिनिधि इससे अंजान हैं?

जी नहीं वो अंजान नहीं हैं, लेकिन जो भी प्रयास किये जा रहे हैं वह नाकाफी साबित हो रहे हैं। जब तक प्रशासन वर्तमान वाहनों की संख्या और स्थिति के हिसाब से योजना बनाकर कार्यान्वित करता है, काफी देर हो चुकी होती है और परिस्थितियां भी बदल चुकी होती हैं।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहर में फ्लाईओवर की भारी कमी है। कुछ वर्ष पहले योजना बनी थी, केवल एक शुरू हो पाई, एक अधूरी हालत में है कई सालों से। पिछले कुछ सालों में एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो स्थिति और भी भयावह है, यहाँ न तो कोई फ्लाईओवर है, न अंडरपास। हास्यास्पद ये है कि नियमित रूप से इतने भारी जाम के बावजूद एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। बमुश्किल किसी किसी चौराहे पर यातायात कर्मी नजर आते हैं, वो भी गौर चौक, एक मूर्ति चौक, हनुमान मंदिर चौक इत्यादि स्थानों पर अस्थाई रूप से।

## यातायात की समस्या के बढ़ाने में निम्न कारकों का भी अत्यधिक योगदान है।

### 1. अपर्याप्त यातायात कर्मी

यातायात कर्मियों की उपस्थिति और हर महत्वपूर्ण चौराहे/सड़क पर प्रभावी कार्यवाही, काफी हद तक समस्या





सुलझा सकती है। लेकिन अधिकतर चौराहों को बंद करके यू-टर्न के भरोसे छोड़ दिया गया है, जो अक्सर ट्रैफिक धीमा करने के साथ साथ भारी जाम का कारण बनते हैं। जैसे गौर चौक पर यातायात दो तरफ से बंद कर आगे यू-टर्न बनाया गया है। यातायात कर्मियों की तैनाती, या ट्रैफिक सिग्नल में लगने वाला खर्च तो बचा, लेकिन इसका परिणाम भयावह है। इसकी वजह से रोज काफी लम्बा जाम लगता है।

## 2. सड़क पर बेतरतीब पार्किंग

शायद ही कोई सड़क हो जिसका एक या दो लेन लोकल ऑटो और कार पार्किंग के लिए उपयोग न होता हो। पतले सेक्टर रोड की बात तो छोड़ दीजिये, 6 लेन सड़क पर भी ट्रैफिक बमुश्किल एक लेन में चल पाता है। सेक्टर 52 से कालिंदीकुंज जाने वाली सड़क इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। सड़क कितनी भी चौड़ी बन जाय, लेकिन उसे अतिक्रमण मुक्त न रखा गया तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

सार्वजनिक बसें और ऑटो जो चलती भी हैं, वो कहीं भी वाहनों को पार्क कर सवारी बैठाने/उतारने लगते हैं। बस स्टॉप बनाने के साथ ही, सड़क से हटके सार्वजनिक वाहन के रुकने की व्यवस्था पर भी जोर देना होगा।

## 3. सड़क किनारे लगने वाले सामाहिक और नियमित बाजार

नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सड़कों पर कब्जा कर नियमित और सामाहिक बाजार लगाया जाता है। बाकायदा इसके लिए पैसे वसूले जाते हैं और बिजली भी दी जाती है। पुरानी सड़कों की तो बात ही क्या है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे नए बसे शहर में भी कई सड़कें बाजार में तब्दील हो गयी हैं, कई सप्ताह के किसी खास दिन हो जाती हैं। यातायात की

समस्या बढ़ने में इनका खासा योगदान है। यदि सेक्टर के अंदर गाड़ियां मंथर गति से जाएंगी तो व्यस्त समय में मुख्य सड़क पर भी इसका असर पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या के बाद भी प्रशासन का अतिक्रमण मुक्त करवाने में अरुचि समझ के परे है।

## 4. फुट ओवरब्रिज की कमी से पैदल सड़क पार करने वाले लोग

अक्सर व्यस्त सड़कों पर लोग जान जोखिम में डाल कर सड़क पार करते हैं। इससे न केवल दुर्घटना का खतरा रहता है, बल्कि गाड़ियों की गति भी काफी धीमी हो जाती है। व्यस्त समय में इसका परिणाम भारी जाम के रूप में मिलता है। प्रशासन और प्राधिकरण अगर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर फुट ओवरब्रिज नहीं बनाते तो यातायात की समस्या सुलझ नहीं पाएगी।

## 5. सार्वजनिक बसों की कमी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे भरी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की अनुपस्थिति आश्चर्यचकित करती है। एक भी बस न चलाना, मेट्रो को दशक तक लालफीताशाही में उलझा देना, जिला प्रशासन, प्राधिकरण और सरकार की यातायात की समस्या सुलझाने में कितनी रूचि है ये बताता है। सार्वजनिक परिवहन की कमी से, लोग निजी वाहनों से जाने को विवश होते हैं। इसके फलस्वरूप सड़क पर गाड़ियों का दबाव काफी बढ़ जाता है और यातायात की समस्या उत्पन्न होती है।

## 6. मेट्रो की सीमित उपलब्धता

मेट्रो की प्लानिंग नोएडा में अच्छी नहीं है। एक्वा लाइन और ब्लू लाइन का इंटरचेंज, अलग अलग टिकट, दुबारा सुरक्षा जांच इत्यादि काफी समय लेते हैं, इसकी वजह से लोग सीधे दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पहुँचने



की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से भी सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ, स्टेशन के आस पास पार्किंग और धीमे ट्रैफिक का कारण बनती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे शहर में तो मेट्रो एक दशक से भी ज्यादा से योजना और डीपीआर स्तर से बाहर ही नहीं निकल पाई है। नोएडा में भी अधिकतर सेक्टर, मेट्रो से दूर हैं।

### 7. अधूरे सड़क

मजे की बात है, यातायात की इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद, कई महत्वपूर्ण सड़क अधूरे हैं। एफएनजी पर छिजारसी के ऊपर फ्लाईओवर की दशकों से योजना ही बन रही है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ऐस सिटी से 130 मीटर जोड़ने वाली सड़क हो, हनुमान मंदिर से सर्वोत्तम स्कूल जाने वाली सड़क या फिर सेक्टर 16 से जीटी रोड जाने वाले रेल ओवरब्रिज। सभी वर्षों से अधूरे हैं, लगातार माँग के बावजूद प्रशासन ने इन्हे पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यहाँ तक की 130 मीटर रोड भी तिलपता चौक से पहले अधूरा है, किसी विचाराधीन मुकदमे की वजह से, लेकिन सरकार इसे सुलझाने के लिए गंभीर नहीं दिखती।

### 8. फ्लाईओवर/अंडरपास की कमी

कई साल पहले सिग्नल फ्री सड़कों को बनाने का काम शुरू हुआ था। इस दिशा में अंडरपास और फ्लाईओवर बनाकर प्रयास होने थे। लेकिन कई साल से ये काम बंद हो गया। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट से दिल्ली जाना चाहें या फिर नोएडा से डीएम ऑफिस। सिग्नल फ्री सड़क की परिकल्पना अंडरपास और फ्लाईओवर की कमी से अधूरी सी लगती है।

### 9. अतिक्रमण

सड़क के एक बड़े भाग पर ऑटो, कार पार्किंग, दुकान, साप्ताहिक बाजार, सब्जी बाजार, रेहड़ी पटरी वालों इत्यादि ने कब्जा कर रखा है। प्रशासन सड़कों को अतिक्रमणमुक्त करने में नाकाम रहा है। ट्रक और बसों की भी बेतरतीब पार्किंग कर सड़क पर कब्जा कर लिया गया है। बिना सड़क को

अतिक्रमणमुक्त किये बेहतर यातायात व्यवस्था की बात करना बेमानी है।

### 10. उल्टा चलना

दुर्घटना और जाम का एक बड़ा कारण सड़क पर उल्टा चलने वाले लोग भी हैं। थोड़ी सी दूरी बचाने के लिए लोग उल्टा आते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ यातायात धीमा होता है बल्कि दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाकर इस पर काबू किया जा सकता है।

### 11. योजना

भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाने की जरूरत है, और समयबद्ध तरीके से उसे पूरा करने की भी जरूरत है। मेट्रो, बस, फ्लाईओवर, अंडरपास, ट्रैफिक सिग्नल, यातायातकर्मियों इत्यादि की कमी साफ इशारा करती है कि समय रहते पर्याप्त विचारमंथन करके योजनाएं नहीं बनाई गयीं, जो योजनाएं बनी भी वो इतनी देरी से कार्यान्वित हुई कि उसका पूरा फायदा नहीं मिला।

कुल मिलाकर, अगर यातायात सुधारना है, तो प्रशासन, प्राधिकरण, यातायात पुलिस को जनता के साथ मिलकर समस्या समझनी पड़ेगी, साथ ही एकीकृत योजना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ यातायात कर्मियों की जनसंख्या, सड़कों की लम्बाई और गाड़ियों की संख्या के हिसाब से बढ़ोत्तरी करनी होगी। सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो के साथ लास्ट मील कनेक्टिविटी के उपाय निश्चित रूप से स्थिति सुधारने में सहायक होंगे।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सड़कों को अतिक्रमण, ऑटो/बस/ट्रक की कहीं रुक जाने की आदत बेतरतीब पार्किंग से बचाना है। इसके बिना शायद कभी सुचारु रूप से चलने वाली यातायात की कल्पना नहीं की जा सकती।



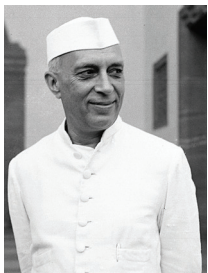


यूपी की लोकसभा सीटों से  
जीत कर 9 प्रधानमंत्रियों ने  
54 साल तक संभाली  
देश की बागडोर,  
सिलसिला अब भी  
जारी



## केंद्र की राजनीति में यूपी की धमक

कहते हैं देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। यह कहावत है ही नहीं हकीकत भी है। क्योंकि देश की आजादी के 74 साल में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, उनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों से जीते और सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। यूपी की लोकसभा सीटों से जीत कर अब तक 9 प्रधानमंत्रियों ने संसद पहुंचे हैं। ये प्रधानमंत्री करीब 54 सालों तक दिल्ली में बैठकर देश की बागडोर संभाली। इनमें सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं। जिसकी शुरुआत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से हुई थी। वहीं, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से ही सांसद हैं।

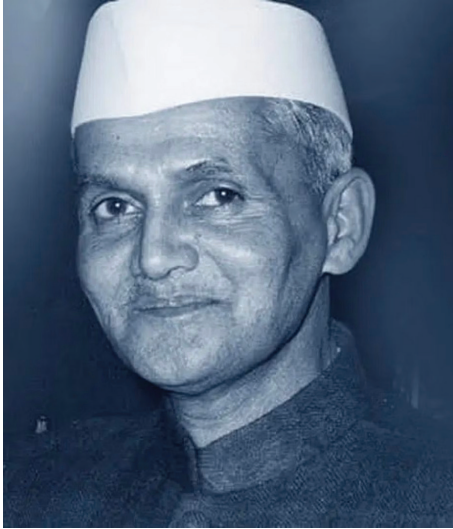


**इलाहाबाद ने दिया था देश को पहला प्रधानमंत्री**

वैसे तो पंडित जवाहर लाल नेहरू 1947 में ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ था। 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब प्रधानमंत्री के लिये कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार

पटेल को सर्वाधिक मत मिले। इसके बाद आचार्य कृपलानी को वोट मिले थे। लेकिन महात्मा गांधी के कहे पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951-1952 में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में जवाहर लाल नेहरू ने अपने जन्म स्थान इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर भारत के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इसके बाद 1957 और

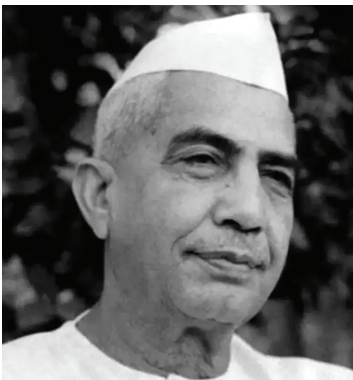
1962 के लोकसभा चुनाव इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली। जवाहर लाल नेहरू अपनी मृत्यु 1964 तक यहीं से सांसद रहे।



#### लाल बहादुर शास्त्री ने 18 महीने तक संभाली देश की बागडोर

1964 में जवाहर लाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री भी इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत कर 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 लगभग 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी। ताशकंद (सोवियत संघ रूस) में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लाल बहादुर की 11 जनवरी 1966 की रात में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी थी।

#### 5 महीने 17 दिन के लिए पीएम बने थे चौधरी चरण सिंह



भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी यूपी की बागपत लोकसभा सीट से सांसद थे। किसान नेता और कई बार विधायक रहे चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री रहे। हाल ही में केंद्र सरकार ने चौधरी चरण

सिंह को भारत रत्न दिया है। वहीं, चौधरी चरण सिंह के भतीजे भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

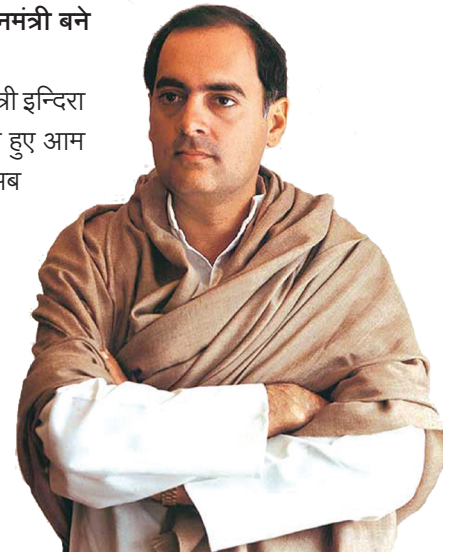
#### पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से थीं सांसद

भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से दो बार सांसद थीं। हालांकि जब वह 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा सदस्य थी। इसके एक साल बाद 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़कर जीतीं और प्रधानमंत्री बनी रहीं। इसी तरह 1971 में हुए चुनाव में भी इसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचीं। हालांकि 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से हार गईं और कांग्रेस की भी सरकार नहीं बन पाई। इसके बाद 1980 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल किया। इस बार इंदिरा गांधी एहतियातन रायबरेली के साथ तत्कालीन आंध्र प्रदेश की मेडक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी दोनों सीटों से चुनाव जीतने के बाद रायबरेली सीट छोड़ दी थी।



#### अमेठी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी

31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस ने इतिहास में अब तक सबसे अधिक 414 सीटें जीतीं। राजीव गांधी अमेठी लोकसभा सीट संसद बनकर प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी का कार्यकाल 1989 तक रहा। राजीव गांधी की राजनीति में रुचि नहीं थी और वह एक एयरलाइन पाइलट की नौकरी करते थे।



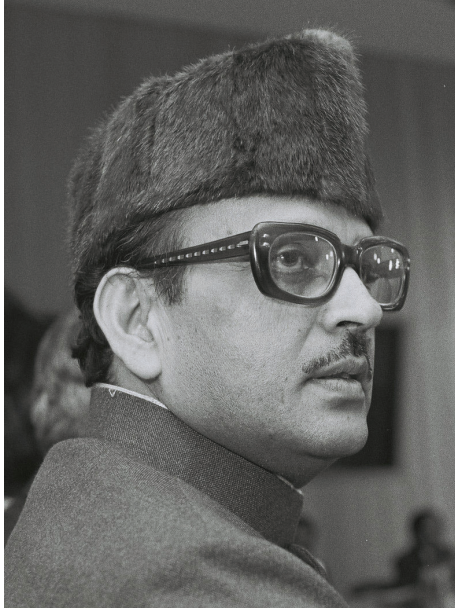
लेकिन 1980 में छोटे भाई संजय

गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मौत के बाद इन्दिरा गांधी को सहयोग देने के लिए राजनीति में सक्रिय हुए थे।

#### 11 महीने 8 दिन तक वीपी सिंह रहे थे प्रधानमंत्री

भारत के 9वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (वीपी सिंह) भी फतेहपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत आंकड़े से दूर रह गई। जबकि वीपी सिंह ने सिंह के राष्ट्रीय मोर्चे (जनता दल) को 146 सीटें मिलीं। बाद में भाजपा और वामदलों के साथ





### पहली बार 13 दिन के लिए पीएम बने थे अटल बिहारी

11वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ लोकसभा सीट से जीत कर 10वें प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली थी। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन तक (16 मई 1996-1 जून 1996) ही प्रधानमंत्री रह सके। इसके बाद 1996 में हुए मध्यावधि चुनाव में भाजपा को 167 सीटें मिलीं और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से जीतकर फिर प्रधानमंत्री बने लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण यह भी कार्यकाल सिर्फ 13 महीने (19 मार्च 1998-19 अक्टूबर 1999) का ही रहा। इसके बाद 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को फिर 182 सीटें मिलीं लेकिन गठबंधन में पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री बने रहे।

मिलकर वीपी सिंह प्रधानमंत्री चुने गए। हालांकि वीपी सिंह सिर्फ 11 महीने 8 दिन (2 दिसम्बर 1989-10 नवंबर 1990) तक ही प्रधानमंत्री बने रहे।

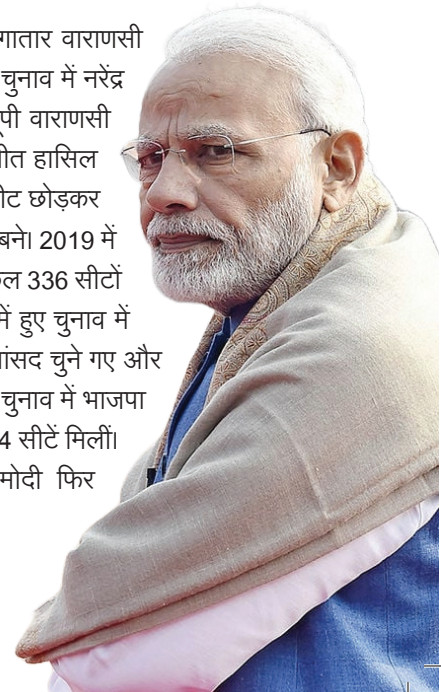
### 6 महीने में चंद्रशेखर को देना पड़ा था पीएम पद से इस्तीफा

भारत के 10वें प्रधानमंत्री बलिया के मूल निवासी चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक लगभग 6 महीने ही प्रधानमंत्री बने रहे। चंद्रशेखर 1989 में अपने गृह क्षेत्र बलिया और बिहार के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा एवं दोनों ही जगह से जीत गए। बाद में उन्होंने महाराजगंज की सीट छोड़ दी थी। हालांकि 3 महीने के बाद ही कांग्रेस ने राजीव की जासूसी कराने के आरोप में चंद्रशेखर की पार्टी से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद चंद्रशेखर को 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।



### जीत की हैट्रिक लगाने के लिए वाराणसी से फिर नरेंद्र मोदी लड़ रहे चुनाव

वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी सीट से सांसद हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा और यूपी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा की सीट छोड़कर वाराणसी सांसद रहे और प्रधानमंत्री बने। 2019 में भाजपा को 282 जबकि NDA को कुल 336 सीटों पर जीत हुई थी। इसी तरह 2019 में हुए चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर वाराणसी सीट से सांसद चुने गए और प्रधानमंत्री की बागडोर संभाली। इस चुनाव में भाजपा को 303 जबकि एनएडी को कुल 354 सीटें मिलीं। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी फिर वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।







# चुनावी खर्च

**ओम प्रकाश सिंह**  
विशेष संवाददाता

आजादी के बाद भारत में 18वीं बार आम चुनाव हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता का सुख पाने के लिए जोर-आजमाइश के साथ वो सभी पैतरे अपना रहे हैं। इसके लिए उम्मीदवार से लेकर पार्टी स्तर पर भी खूब पैसे उड़ाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के साथ पारंपरिक तरीके से प्रचार कर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। जिसकी वजह से हर चुनाव में खर्च का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 1951 से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक चुनावी खर्च का आंकड़ा करीब 900 गुना बढ़ गया है। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 17 हजार 930 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अनुमानतः यह आंकड़ा 1300 गुना बढ़ने की उम्मीद है। ये आंकड़े चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार हैं।

## पहली बार 10.5 करोड़ रुपये चुनाव में हुए थे खर्च

जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो सर्वसम्मति से बिना चुनाव के ही जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया था। 1950 में संविधान लागू होने के बाद देश में पहली बार 1951-1952 में पहली बार आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में करीब 10.5 करोड़ और एक वोटर पर लगभग 1.67 रुपये खर्च हुए थे।

## सबसे कम खर्च 1957 चुनाव में हुआ था

वहीं, दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में 504 सीटों पर हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और जवाहर लाल नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में 1952 के अपेक्षा चुनावी खर्च आधा हो गया था। इस चुनाव में 5.9 करोड़ प्रति मतदाता पर करीब 30 पैसे ही खर्च हुए थे।

## सिर्फ 6 दिन में हो गए थे चुनाव

1962 में हुआ तीसरा लोकसभा चुनाव सिर्फ 6 दिन में ही संपन्न हो गया था। 19 से 25 फरवरी 1962 के बीच में पूरे देश में चुनाव कराए गए थे। 508 सीटों पर हुए इस चुनाव में कांग्रेस ने 361 जीतीं और फिर जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में 21 करोड़ 63 लाख 569 मतदाता पंजीकृत थे और 55.42 फीसदी वोटर्स ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इस चुनाव में करीब 7.3 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इसके अनुसार प्रति वोटर्स पर लगभग 34 पैसे खर्च हुए थे।



### 1967 में सबसे कम समय में चुनाव हुआ था संपन्न

1967 में हुआ चौथा लोकसभा चुनाव इतिहास चुनाव था। अब तक इतिहास में सबसे कम दिनों में चुनाव हुआ था। सिर्फ 4 दिनों में यह चुनाव संपन्न हो गया था। 17 से 21 फरवरी 1967 के बीच 528 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 283 सीटें जीतीं और इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनीं। इस चुनाव में 10.8 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो पिछले चुनाव से 3.5 करोड़ रुपये खर्च हुआ। इस चुनाव में करीब 250,207,401 मतदाता थे, जिसमें 61.04 फीसद ने मतदान किया था। इस तरह करीब 42 पैसे प्रति मतदाता पर खर्च हुए थे।

पांचवी लोकसभा चुनाव 1971 में 521 सीटों पर हुआ था। 1 से 10 मार्च 1971 के बीच हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आर) ने 382 सीटें जीतने में कामयाब रही और दोबारा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। इस चुनाव में 11.6 करोड़ रुपये हुए खर्च हुए थे। जबकि कुल 274,189,132 मतदाता रजिस्टर्ड थे, वहीं 55.27 वोटर्स ने मतधिकार प्रयोग किया था। इस चुनाव में 42 पैसे से अधिक एक वोटर पर खर्च हुआ था।

छठी लोकसभा का चुनाव 16 से 20 मार्च 1977 के बीच हुए थे। यह चुनाव आपातकालीन अवधि के दौरान हुए थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल के घोषित होने के कारण इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में गठबंधन जनता दल से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने गए। देश में यह पहली बार था, जब गांधी परिवार के हाथ से सत्ता गई थी। इस चुनाव में 23 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। जोकि पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2

गुना था। 544 सीटों पर हुए चुनाव में 321,174,327 वोटर पंजीकृत थे, जिसमें से 60.49 फीसद मतदाताओं ने वोट दिया था। इस तरह करीब 71 पैसे एक वोटर पर खर्च हुए थे।

### तीसरी बार

देश में सातवां लोकसभा चुनाव सिर्फ तीन साल बाद 1980 में हुए। 531 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस (आर) ने 353 सीट जीतीं और तीसरी बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। इस चुनाव में खर्च करीब दोगुना बढ़ गया। इस चुनाव में 54.8 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिसमें पंजीकृत 356,205,329 मतदाता में से 56.92 ने मतदान किया था। इस चुनाव में एक वोटर पर 1.53 रुपये खर्च हुए थे।

### 1984 में 63.56 मतदाताओं ने किया था मतदान

इसी तरह 1984 में हुए आठवें लोकसभा चुनाव में 81.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव कुमार प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 516 सीटों में से 404 सीटें जीतीं थीं। इस चुनाव में 379,540,608 वोटर रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 63.56 फीसद ने मतदान किया था। इस चुनाव में एक वोटर पर लगभग 2.15 रुपये खर्च हुए थे।

### 1989 में एक वोटर पर खर्च हुए थे 3.09 रुपये

देश में नौवां लोकसभा चुनाव 1989 में चुनाव हुआ, जिसमें चुनाव खर्च







करीब दोगुना बढ़ गया. 543 सीटों पर हुए इस चुनाव में 154.2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इस चुनाव में कुल 498,906,129 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 61.95 ने मतदान किया था. इस चुनाव में एक वोट पर करीब 3.09 पैसे खर्च हुए थे. वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी.

#### **11वीं लोकसभा चुनाव में खर्च हुए थे 359.1 करोड़**

देश में 11वां लोकसभा चुनाव 16 महीने बाद ही हुआ था. 523 सीटों पर हुए चुनाव में 232 सीटें जीतकर सरकार बनाई और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए. इस चुनाव में जमकर पैसा खर्च हुआ. इस चुनाव में 359.1 करोड़ रुपये खर्च हुए. पिछले चुनाव के मुकाबले 204 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए. जबकि देश में रजिस्टर्ड मतदाता 498,363,801 थे, जबकि 56.73 ने मतदान किया. इस तरह 7.32 रुपये एक मतदाता पर खर्च हुए.

#### **1997 में चुनावी खर्च ने पार किया था 500 करोड़ का आंकड़ा**

वहीं, 1997 में हुए 12वें लोकसभा चुनाव में 597.3 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री बने. इसके बाद 2 साल बाद ही देश में तेरवहीं लोकसभा चुनाव 1998 में हुआ, जिसमें 666.2 करोड़ रुपये खर्च हुए. यह भी सरकार नहीं ज्यादा दिन नहीं चल पाई और फिर 1999 में चौदहवीं लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें 947.7 करोड़ रुपये खर्च हुए. इन तीनों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी और अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने.

#### **एक वोट पर औसतन 15 रुपये से अधिक खर्च हुए**

14वां लोकसभा चुनाव 2004 में 20 अप्रैल और 10 मई 2004 के बीच चार चरणों में हुआ था. 543 सदस्यों को चुनने के लिए 670 मिलियन से अधिक लोग वोट रजिस्टर्ड थे. पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से चुनाव कराया गया था. इस चुनाव में 145 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने. इस चुनाव में 1016.1 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस चुनाव में प्रति मतदाता

पर 15 रुपये से अधिक खर्च हुए थे. इसी तरह 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में 1114.4 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. इस चुनाव में 716,985,101 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 58.21 फीसद ने मतदान किया था.

#### **पहली बार 9 चरण में हुए चुनाव से बढ़ा खर्च**

16वां लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था. पहली बार देश में 9 चरणों में मतदान कराया गया था. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीत कर सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. इस चुनाव में खर्च का आंकड़ा तेजी से बढ़ गया. 2014 लोकसभा चुनाव में 3870.3 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस चुनाव में सबसे अधिक खर्च के साथ मतदान फीसद से भी सबसे अधिक हुआ था, 64 फीसद मतदाताओं ने मतदान किया.

#### **90 करोड़ मतदाताओं के लिए 9000 करोड़ हुए खर्च**

भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 303 सीटें जीतीं. इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन चुनावी खर्च में बेहताशा वृद्धि हो गई. इस चुनाव में 9000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. जोकि पिछले चुनाव के अपेक्षा लगभग तीन गुना अधिक था. इस चुनाव में 90 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 67.4 फीसद ने मतदान किया था. इस चुनाव में एक वोट पर करीब 100 रुपये खर्च हुए.

#### **इस बार 13000 करोड़ पर कर सकता है चुनावी खर्च**

वहीं, 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं. इस चुनाव में धुआंधार खर्च प्रचार से लेकर विभिन्न गतिविधियों में किए जा रहे हैं. पिछले चुनाव में खर्च हुए आंकड़ों से पता चल रहा है कि इस बार का चुनाव खर्च 13000 करोड़ से अधिक पहुंच सकता है. भाजपा से लेकर कांग्रेस करोड़ों रुपये का विज्ञापन दे रही है. वहीं, स्टार प्रचारकों पर भी करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं. बड़े-बड़े नेताहेलिकॉप्टर और हवाई जहाज से पहुंचकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. वहीं, इस बार करीब 96.8 करोड़ मतदाता देश में हैं, जो प्रधानमंत्री चुनेंगे.





# PARTNER WITH MADE BY INDIA

Expand & Accelerate Your Business's Growth



No Capital Investment required



Partner with the Market Leader

✉ sales@madebyindia.com

☎ 07011412854

🌐 www.madebyindia.com



## GET YOUR DYNAMIC WEBSITE WITH CMS PANEL

### Our Best Service

- 4-5 CUSTOM PAGES
- WHATSAPP CHAT INTEGRATION
- CONTACT FORM FOR LEAD GENERATION
- GOOGLE MAP INTEGRATION
- MOBILE FRIENDLY
- SEO FRIENDLY

☎ +91 7982133887

🌐 www.webcadenceindia.com

✉ asha@webcadenceindia.com



\*\*TERMS & CONDITIONS APPLY

# कैराना को कौन पसंद है?



संदीप ओझा  
संपादक

कैराना लोकसभा सीट पर 17 लाख 22 मतदाताओं ने पहले चरण में 19 अप्रैल को हुए मतदान में 14 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया है। 14 प्रत्याशियों में 6 निर्दलीय भी हैं, जिन्होंने इस बार सांसद बनने के लिए अपना भाग्य अजमाया है। मतदान यहां पर भले ही चुप्पे-साधे हुए हैं, लेकिन सभी प्रत्याशियों का अपना गणित है। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी एक दूसरे का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कैराना लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख 22 हजार 432 मतदाता हैं, जिसमें अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 8 लाख 518 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 9 लाख 21 हजार 820 है, अन्य मतदाताओं की संख्या 871 है।

## क्या है कैराना का समीकरण?

कैराना पर देश के साथ ही प्रदेश की नजर टिकी होती है। कैराना लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी हैं तो सपा की तरफ से हसन परिवार की इकरा हसन हैं, इकरा हसन ने इस बार मीडिया

और सोशल मीडिया में खूब प्रशंसा बटोरी है, जिसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि इन्हीं दोनों प्रत्याशियों में टक्कर होगी। हालांकि बसपा से श्रीपाल राणा, आजाद अधिकार सेना से ओमवीर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जाहिद, पीपल्स से नंद किशोर, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी से प्रीति कश्यप, अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी से विक्रम सैनी भी मैदान हैं। कहा तो ये भी जा रहा है बसपा और दूसरी पार्टी का समीकरण भी खेला बिगाड़ सकता है।

## कैसे रहा मतदान का प्रतिशत?

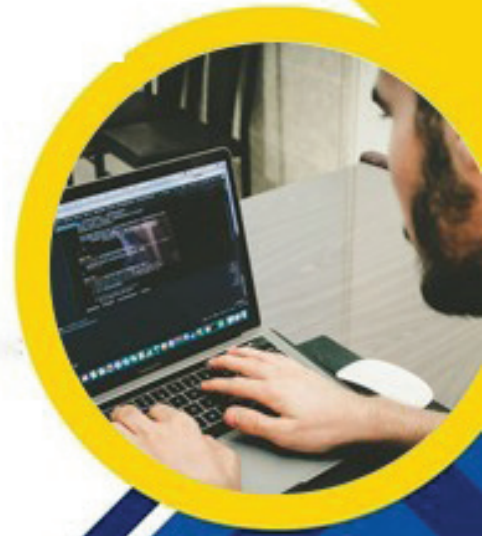
कैराना लोकसभा सीट पर हुए मतदान में 61.87 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मतधिकार का प्रयोग कर 14 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में कैद किया। लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा नकुड़ विधानसभा सीट पर 70.03 तो गंगोह में 63.88 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अलावा शामली में सबसे कम 55.45 प्रतिशत मतदान हुआ। थानाभवन में 57.98, कैराना में 57.02 प्रतिशत मतदान हुआ।



# SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY

## Our Best Service

- ⦿ Lead Manegment
- ⦿ Help desk Manegment
- ⦿ QR Code Generation
- ⦿ School Manegment
- ⦿ Inventory Manegment



+91 7982133887

[www.webcadenceindia.com](http://www.webcadenceindia.com)

[asha@webcadenceindia.com](mailto:asha@webcadenceindia.com)

## Email Marketing

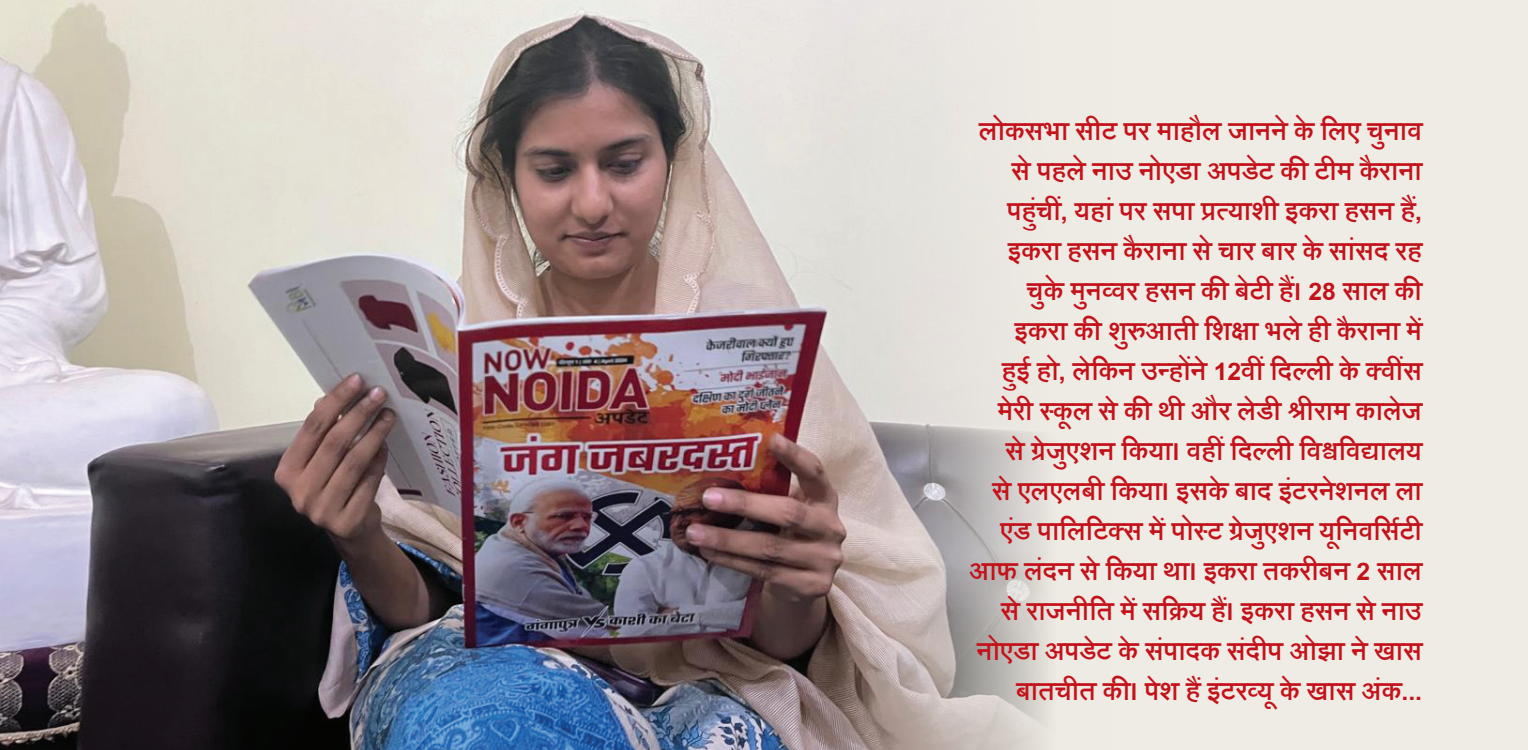


➤ Domain

➤ Bulk Whatsapp

➤ Bulk SMS/ Bulk Email

➤ Coporate Email



लोकसभा सीट पर माहौल जानने के लिए चुनाव से पहले नाउ नोएडा अपडेट की टीम कैराना पहुंचीं, यहां पर सपा प्रत्याशी इकरा हसन हैं, इकरा हसन कैराना से चार बार के सांसद रह चुके मुनव्वर हसन की बेटी हैं। 28 साल की इकरा की शुरुआती शिक्षा भले ही कैराना में हुई हो, लेकिन उन्होंने 12वीं दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से की थी और लेडी श्रीराम कालेज से ग्रेजुएशन किया। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। इसके बाद इंटरनेशनल ला एंड पालिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी आफ लंदन से किया था। इकरा तकरीबन 2 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इकरा हसन से नाउ नोएडा अपडेट के संपादक संदीप ओझा ने खास बातचीत की। पेश हैं इंटरव्यू के खास अंक...

**संदीप ओझा-** राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे हुई और आपने शिक्षा-दिक्षा कहां से ली?

**इकरा हसन-** साल 2022 में मेरे भाई को झूठे मुकदमें में जेल में डाल दिया गया था। जब मेरे भाई जेलमें थे तो उनके चुनाव के प्रचार का काम मैंने देखा, राजनीति में आने की पहले से प्लानिंग नहीं थी लेकिन परिवार राजनीति में रहा है तो मेरी रुचि जरूर रही है, तो मैं सिर्फ मैनेजमेंट संभालने तक ही सोच थी, वहीं तक मैं संतुष्ट भी थी लेकिन जब मेरे भाई को झूठे मुकदमें में जेल में डाल दिया गया तभी से मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो गई।

**संदीप ओझा-** अभी अपने प्रचार का मैनेजमेंट कैसे कर रही हैं, क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में आपको काफी समस्या का भी सामना करना पड़ता होगा।

**इकरा हसन-** कैराना लोकसभा सीट में पहले चरण में चुनाव हो रहा है, प्रचार करना भी जरूरी है। अभी तो नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। रमजान के साथ प्रचार के काम को किसी तरह मैनेज करना पड़ रहा है। हिम्मत और मेहनत से सफलता मिलेगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है।

**संदीप ओझा-** आपकी नज़र में कैराना लोकसभा क्षेत्र में क्या-क्या प्रमुख समस्याएं हैं, अगर जनता ने आपको सांसद चुना तो उन समस्याओं पर आप प्रमुखता के साथ काम करेंगी।

**इकरा हसन-** क्षेत्र का विकास अहम है, ग्रामीण इलाके में कई कमियां हैं, जिन पर काम करना बेहद आवश्यक है। ग्रामीण इलाकों में रोड़, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार प्रमुख समस्याएं हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र

में बड़ी तादात में बुनकर समाज मौजूद हैं, उनके लिए इंडस्ट्री लगवाने का काम है, जिससे रोजगार की समस्या खत्म होगी, क्योंकि यहां के लोग रोजगार के लिए दिल्ली-एनसीआर और पानीपत की तरफ जाते हैं। इसके अलावा मेरी नज़र में महिलाओं के एजुकेशन पर हमारा विशेष जोर रहेगा।

**संदीप-** आपकी लड़ाई यहां पर बीजेपी-आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी है, उनके स्टार प्रचारक यहां आकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी के तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक अभी तक कैराना नहीं पहुंचा?

**इकरा हसन-** स्टार प्रचारक आएंगे, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो किसी नेशनल मुद्दे पर नहीं है बल्कि लोकल मुद्दों पर हो रहा है। यहां के मतदाता अपनी समस्या को लेकर मतदान करेंगे। स्थानीय लोगों के 36 बिरादरी का इस पर मुझे समर्थन मिल रहा है।

**संदीप ओझा-** एनडीए तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रही है?

**इकरा हसन-** साल 2014 में मोदी के चेहरे पर वोट मांगा गया, साल 2019 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगा गया, लेकिन इससे आम लोगों का कुछ भला तो हुआ नहीं, इसलिए जनता इस पर अपने लोकल मुद्दों पर वोट करना चाहती है, क्योंकि हर काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ तो करेंगे नहीं। यही कारण है कि यहां के लोगों में उदासीनता है, क्योंकि यहां से जो तत्कालीन सांसद हैं उन्होंने तो कुछ काम लोगों के लिए किया नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लिया और पांच साल गायब थे। जनता इस बार पूरी तरह से बदलाव के मूड में है।



संदीप ओझा- अगर पश्चिम यूपी और कैराना लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर खेती करते हैं। लंबे समय से किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। आप उनके लिए कैसे काम करेंगी।

**इकरा हसन-** यहां पर गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है, यहां की मिल पर किसानों का बकाया है, इसका निस्तारण नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण तत्कालीन सरकार है, जो जानबूझ कर किसानों के समस्याओं का निस्तारण नहीं करवा रही है। मैं अगर प्रतिनिधि चुनी गई तो मैं उनकी आवाज पूरे जोर के साथ संसद में उठाऊंगी। हमारे जिले में तीन महीने तक धरना चला था, उसमें ना तो बीजेपी का कोई भी जनप्रतिनिधि पहुंचा, ना ही संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए मैंने सुना। अगर कोई सांसद चाहे तो पूरे देश की तरफ अपने जिले की समस्या को उठा सकता है और सरकार को उसकी समस्या को सुनना होगा लेकिन कोई भी किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से नहीं उठा रहा है।

संदीप ओझा- आरएलडी इस बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, जाट समाज को आप कैसे अपनी ओर लाएंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जाट समाज हमेशा से आरएलडी को सपोर्ट करता रहा है।  
**इकरा हसन-** आरएलडी को तोड़कर भले ही एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया गया हो लेकिन अभी तक दलों का मेल तो हो गया है, दिलों का मेल नहीं हो पाया है। क्योंकि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, यहां के लोग बीजेपी की विचारधारा को समर्थन नहीं देते, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है सभी समाज से मुझे समर्थन मिल रहा है। अगर बीजेपी के विचारधारा की बात करें तो वो हमेशा से किसान विरोधी रहे हैं। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी सरकार से सारा लाभ पूंजीपतियों को हो रहा है, सारी सरकारी चीजें बेची जा रही हैं सब कुछ पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। इससे हम और पीछे जा रहे हैं। क्योंकि पब्लिक सेक्टर से ही जनता को लाभ मिलता है वहां दर कम होती हैं और सुविधाएं ज्यादा होती हैं। जिससे लोगों को लाभ होता है।







ओम प्रकाश सिंह  
विशेष संवाददाता

# मंगलसूत्र और संविधान पर बिछी बिसात



देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। आजादी के बाद 18वीं बार हो रहे आम चुनाव में सियासतदानों ने बिसात बिछा दी है। पूरे देश में इस समय राजनीतिक माहौल है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत का हैट्रिक लगाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनावी मैदान में पूरे जोश-खरोश से लगी हुई है। भाजपा अपने गठबंधन के साथ 400 पार का प्लान बनाकर विपक्ष का सूपड़ा साफ करने की बात कह रही है। वहीं, एक दशक से सत्ता से दूर कांग्रेस अन्य दलों के सहारे वापसी करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों के नेता भाजपा के विजयी रथ रोकने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस और भाजपा में 'जुबानी वार' शुरू हो गया है। यह जुबानी वार मेनिफेस्टो से शुरू हुआ है, जो अब अलग ही रूप ले रहा है। चुनावी जनसभा में बाकी मुद्दे छोड़कर मंगलसूत्र, संविधान और परिवारवाद की ही नेता बातें कर रहे हैं।





### कांग्रेस के न्याय पत्र में क्या है?

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। ये मनिफेस्टो 5 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर आधारित है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियां, जातिगत जनगणना, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपये सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और PMLA कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की 'गारंटी' दी है। 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। 'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही 'नारी न्याय' के अंतर्गत 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

### राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को बताया भारत का एक्स-रे

जहां चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ सहयोगी दलों के नेता अखिलेश यादव व अन्य चुनावी जनसभा में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भाजपा जीती तो संविधान बदला जाएगा। इसलिए जनता से अपील कर रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए मतदान करें। भाजपा के कुछ नेताओं ने संविधान को लेकर कुछ बातें कहीं थीं, जिसके बाद विपक्ष ने इसे उठा लिया। वहीं, राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर अपने दोस्त अडानी को देश की संपत्ति बेचने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वह गरीबों को उनका हक दिलाए। इसके साथ ही मुस्लिम समाज को भी हक दिलाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी बीते दिनों ने एक चुनावी

**राहुल गांधी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वह गरीबों को उनका हक दिलाए। इसके साथ ही मुस्लिम समाज को भी हक दिलाने की बात कह रहे हैं**

जनसभा में कहा था कि जातिगत जनगणना हिंदुस्तान का एक्स-रे है। सरकार आते ही जातिगत जनगणना कराएंगे, ताकि सबको पता चले कि देश में किसकी-कितनी भागीदारी है। इसके साथ ही गरीबों में संपत्ति बांटने की बात कही थी।

### आखिर क्यों महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात हुई

राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के मनिफेस्टो का भाजपा ने काट निकालना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण से की। पीएम मोदी ने कई जनसभाओं में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सर्वे कराकर पता कराएगी कि किसके पास कितनी गाड़ी, सोना, घर और संपत्ति है, उसको कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। इसका मतलब है कांग्रेस नया कानून लाकर माताओं-बहनों की संपत्ति यानी उनके मंगलसूत्र छीन लेगी। पीएम मोदी द्वारा यह बयान देते ही भाजपा के अन्य नेताओं ने उठा लिया। इसके बाद मंगलसूत्र पर राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेस और भाजपा के नेता मंगलसूत्र के इर्द बाट कर रहे हैं।

### प्रियंका गांधी ने खेला 'भावुक' कार्ड

पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर विपक्ष एकजुट हो गया है। यहां तक चुनावी लड़ाई पर्सनल हो गई। प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके

मंगलसूत्र छीने? जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी मां का मंगलसूत्र (राजीव गांधी) इस देश को कुर्बान हुआ है.” अगर मोदी जी ‘मंगलसूत्र’ का महत्व समझते तो ऐसी बातें नहीं कहते. जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने महिलाओं की बचत छीन ली. किसानों के विरोध के दौरान 600 किसानों की जान चली गई, क्या मोदी जी ने उन विधवाओं के ‘मंगलसूत्र’ के बारे में सोचा? जब मणिपुर में एक महिला को नग्न कर घुमाया गया, तब मोदी जी चुप थे, क्या उन्होंने उनके ‘मंगलसूत्र’ के बारे में सोचा? आज वह वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कह रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वे डरकर वोट करें.”

### मुस्लिम समाज पीएम ने ऐसे साधा

वहीं, कांग्रेस और सपा के पारंपरिक वोटर माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया. जब वह पसमांदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करते हैं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं. पीएम मोदी ने तीन तलाक का मुद्दा भी उठाया कहा कि मुस्लिम बेटियों का जीवन तबाह होने से मोदी सरकार ने बचाया. इसके साथ ही कहा कि सउदी के क्राउन प्रिंस से बात कर वीजा नियमों को आसान बनाया, जिससे महिलाएं भी बिना महरम हज जाने की अनुमति मिली.

### संविधान बदलने वाले बयान की क्या है सच्चाई?

देश में संविधान बचाओ का नारा नया नहीं है. जो भी दल विपक्ष में



रहता है उसे संविधान की चिंता कुछ ज्यादा होने लगती है। इस बार तो इंडी गठबंधन शामिल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी लगातार संविधान बचाओ के नारे बुलंद कर रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी संविधान के खतरे में होने की बात कर रहे हैं। इसके विपरीत अब सत्ता पक्ष यानी भाजपा के नेता भी यही राग







**राजद्रोह अधिनियम को हटाकर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रावधान लाए गए, इस कानून में अपराध का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है**

अलापने लगे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो संविधान में जो हक पिछड़ों और अनुसूचित जातियों को मिला है वो खतरे में पड़ जाएगा. मतदाता किसकी बात पर यकीन करें, उसके लिए मुश्किल हो गई है।



कांग्रेस और राहुल गांधी बार-बार ये कह कह रहे हैं कि भाजपा इसीलिए 400 सीट चाहती है ताकि वह संविधान को बदल सके और आरक्षण खत्म कर सके। जबकि मोदी पूरा दम लगाकर ये कह रहे हैं कि संविधान को कोई माई का लाल संविधान बदल नहीं सकता। हां, यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वह SC, ST, OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी.

#### **मोदी सरकार में संविधान में संशोधन**

मोदी सरकार 124वां संविधान संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया. राजद्रोह अधिनियम को हटाकर देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रावधान लाए गए, इस कानून में अपराध का दायरा बहुत बड़ा रखा गया है। अभी तक किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था पर अब 60 से 90 दिन तक पुलिस किसी को भी हिरासत में रख सकती है. इसके अलावा

#### **कांग्रेस के शासन में कितनी बार संविधान में हुआ संसाधन**

देश में अब तक सबसे अधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया. इसलिए सबसे अधिक संविधान संशोधन कांग्रेस के शासन में सबसे अधिक करीब सौ से संशोधन हुए हैं। बाबा साहब के बनाए संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी. क्योंकि आरक्षण के मूल में दलित जातियों को बाकी सबके बराबरी में लाने का भाव था। लेकिन कांग्रेस ने कई राज्यों में मुसलमानों को अल्पसंख्यक और ओबीसी कहकर आरक्षण देने की कोशिश की। कर्नाटक में तो सभी पठान और मौलवी भी ओबीसी आरक्षण दिया गया. कांग्रेस के नाम 100 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का कारनामा भी शामिल है. इंदिरा गांधी के नाम सबसे बड़ा संविधान संशोधन करने का कारनामा दर्ज है. इमरजेंसी लागू करने के लिए संविधान को तोड़-मरोड़ दिया था.





निर्मल गौड़,  
उप संपादक

# चुनावी दण में VIP उम्मीदवार



देश में 543 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दो चरण के मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में 120 और दूसरे में 80 सीटों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अभी 343 सीटों पर मतदान बाकी है। इनमें से अधिकतर सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों ने उम्मीदवार घोषित किए हैं। भाजपा ने सबसे अधिक 405 सीटों पर उम्मीदवारों को घोषित कर दिए हैं। वहीं, एनडीए के सहयोगी दल भी 23 उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस तरह एनडीए ने 428 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। जबकि यूपी के रायबरेली, कैसरगंज समेत 115 सीटों पर उम्मीदवारों के घोषणा होना बाकी है।



## भाजपा के बड़े चहेरे

भारतीय जनता पार्टी ने जीत का हैट्रिक लगाने के लिए इस बार कम रिस्क लिया है। भाजपा ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हैं। इनमें से अधिक तो सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार

भी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्मृति इरानी मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने बॉलीवुड की भी एंट्री दी है। हिमाचल के मंडी से जहां कंगना रनौत और मेरठ से रामायण के राम अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है।



प्रत्याशी	पार्टी	लोकसभा सीट
नरेंद्र मोदी	बीजेपी	वाराणसी
राजनाथ सिंह	बीजेपी	लखनऊ
अमित शाह	बीजेपी	गांधी नगर
स्मृति ईरानी	बीजेपी	अमेठी
किरेन रिजिजू	बीजेपी	अरुणाचल पश्चिम
अनुराग ठाकुर	बीजेपी	हमीरपुर
अजय टमटा	बीजेपी	अल्मोड़ा
गिरिराज सिंह	बीजेपी	बेगूसराय
महेंद्र नाथ पांडेय	बीजेपी	चंदौली
प्रल्हाद जोशी	बीजेपी	धारवाड़
रामशंकर कठेरिया	बीजेपी	इटावा
साध्वी निरंजन ज्योति	बीजेपी	फतेहपुर
ज्योतिरादित्य सिंधिया	बीजेपी	गुना-शिवपुरी
त्रिवेंद्र सिंह रावत	बीजेपी	हरिद्वार
कंगना रानौत	बीजेपी	मंडी
हेमा मालिनी	बीजेपी	मथुरा
पीयूष गोयल	बीजेपी	मुंबई उत्तर
संवित पात्रा	बीजेपी	पुरी
मेनका गांधी	बीजेपी	सुलतानपुर
साक्षी महाराज	बीजेपी	उन्नाव

## कांग्रेस 300 से अधिक सीटों पर लड़ रही चुनाव

इंडी गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 300 से 320 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जिसमें से 240 सीटों से अधिक उम्मीदवार उतार चुकी है। यूपी में 80, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी (सपा), बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और लेफ्ट, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) और शिवसेना (यूबीटी) के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है। कांग्रेस यूपी में 17, बिहार में नौ और महाराष्ट्र में 17 सीटों यानि 168 सीटों वाले तीन राज्यों में 43



सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ दो सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस की गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी पर संशय बरकरार है। कांग्रेस ने 144 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार उतारे हैं।

### कांग्रेस के बड़े उम्मीदवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी फिर से मैदान में हैं। जबकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर अभी संशय बना हुआ है। वहीं, सोनिया गांधी इस बार प्रत्याशी नहीं हैं, वह राज्यसभा से सांसद निर्वाचित हो चुकी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कन्हैया कुमार सहित कई नामचीन हस्तियों को मैदान में उतारा है।

प्रत्याशी	पार्टी	लोकसभा सीट
राहुल गांधी	कांग्रेस	वायनाड
दानिश अली	कांग्रेस	अमरोहा
अधीर रंजन चौधरी	कांग्रेस	बहरामपुर
मनीष तिवारी	कांग्रेस	चंडीगढ़
नकुलनाथ	कांग्रेस	छिंदवाड़ा
डॉली शर्मा	कांग्रेस	गाजियाबाद
दिग्विजय सिंह	कांग्रेस	राजगढ़
भूपेश बघेल	कांग्रेस	राजनांदगांव
इमरान मसूद	कांग्रेस	सहारनपुर
कीर्ति चिदंबरम	कांग्रेस	शिवगंगा
डॉ. शशि थरूर	कांग्रेस	तिरुअनंतपुरम

## सपा ने 62 में से 60 पर उतारे उम्मीदवार

लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी कुल 62 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। 17 सीट कांग्रेस पार्टी को दिए गए हैं। केवल भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दी गई है। कांग्रेस ने 17 में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है।

### सपा उम्मीदवारों की सूची

प्रत्याशी	पार्टी	लोकसभा सीट
अखिलेश यादव	सपा	कन्नौज
डिंपल यादव	सपा	मैनपुरी
अक्षय यादव	सपा	फिरोजाबाद
आदित्य यादव	सपा	बदायूं
इकरा हसन	सपा	कैराना
रविदास मेहरोत्रा	सपा	लखनऊ
अनु टंडन	सपा	उन्नाव
अफजाल अंसारी	सपा	गाजीपुर
अजय राय	सपा	वाराणसी



## यूपी से बसपा उम्मीदवारों की सूची

इस बार बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ रही हैं। बसपा ने 80 में से अभी तक 54 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बाकी हैं।

- |   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 सहारनपुर माजिद अली                        | 16 हाथरस (एससी) हेमबाबू धनगर      | 31 हरदोई (एससी)                                   |
| 2 कैराना श्रीपाल सिंह                       | 17 मथुरा सुरेश सिंह               | 32 मिथिख (एससी)                                   |
| 3 मुजफ्फरनगर दारा सिंह प्रजापति             | 18 आगरा (एससी) पूजा अमरोही        | 33 उन्नाव अशोक कुमार पांडेय                       |
| 4 बिजनौर चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह              | 19 फतेहपुर सीकरी रामनिवास शर्मा   | 34 मोहनलालगंज (एससी) राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान |
| 5 नगीना (एससी) सुरेंद्र पाल सिंह            | 20 फिरोजाबाद सत्येंद्र जैन सौली   | 35 लखनऊ सरवर मलिक                                 |
| 6 मुरादाबाद इरफान सैफी                      | 21 मैनपुरी शिव प्रसाद यादव        | 36 रायबरेली                                       |
| 7 रामपुर जीशान खान                          | 22 एटा मो. इरफान एडवोकेट          | 37 अमेठी  |
| 8 संभल शौलत अली                             | 23 बदायूं मुस्लिम खान             | 38 सुल्तानपुर उदराज वर्मा                         |
| 9 अमरोहा मुजाहिद हुसैन                      | 24 आंवला आबिद अली                 | 39 प्रतापगढ़                                      |
| 10 मेरठ देवव्रत त्यागी                      | 25 बरेली छोटेलाल गंगवार           | 40 फर्रुखाबाद क्रांति पांडेय                      |
| 11 बागपत प्रवीण बंसल                        | 26 पीलीभीत अनीस अहमद खां फूल बाबू | 41 इटावा (एससी) सारिका सिंह बघेल                  |
| 12 गाजियाबाद ठाकुर नंद किशोर पुंडीर         | 27 शाहजहांपुर डॉ. दोदराम वर्मा    | 42 कन्नौज इमरान बिन जफर                           |
| 13 गौतम बुद्ध नगर राजेंद्र सिंह सोलंकी      | 28 खीरी अंशय कालरा रॉकी           | 43 कानपुर कुलदीप भदौरिया                          |
| 14 बुलंदशहर (एससी) गिरीश चंद्र जाटव         | 29 धौरहरा श्याम किशोर अवस्थी      | 44 अकबरपुर राजेश कुमार द्विवेदी                   |
| 15 अलीगढ़ हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय | 30 सीतापुर                        |   |





- 45 जालौन (एससी) सुरेश चंद्र गौतम
- 46 झांसी
- 47 हमीरपुर
- 48 बांदा मयंक द्विवेदी
- 49 फतेहपुर डॉक्टर मनीष सिंह
- 50 कौशाम्बी (एससी) शुभ नारायण
- 51 फूलपुर
- 52 प्रयागराज
- 53 बाराबंकी (एससी)
- 54 फैजाबाद सच्चिदानंद पांडेय
- 55 अम्बेडकरनगर
- 56 बहराइच (एससी)
- 57 कैसरगंज
- 58 श्रावस्ती
- 59 गोंडा
- 60 डुमरियागंज ख्वाजा समसुद्दीन
- 61 बस्ती दयाशंकर मिश्रा
- 62 संतकबीर नगर मोहम्मद आलम
- 63 महाराजगंज

- 64 गोरखपुर जावेद सिमनानी
- 65 कुशीनगर
- 66 देवरिया
- 67 बांसगांव (एससी)
- 68 लालगंज (एससी) इंदु चौधरी
- 69 आजमगढ़ भीम राजभर
- 70 घोसी बालकृष्ण चौहान
- 71 सलेमपुर
- 72 बलिया ललन सिंह यादव
- 73 जौनपुर श्रीकला सिंह
- 74 मछलीशहर (एससी)
- 75 गाजीपुर उमेश कुमार सिंह
- 76 चन्दौली सत्येंद्र कुमार मोर्य
- 77 वाराणसी- सैयद नियाज अली.
- 78 भदोही
- 79 मिर्जापुर मनीष त्रिपाठी
- 80 राबर्ट्सगंज (एससी) धनेश्वर गौतम  
एडवा







**ऋषभकान्त छाबड़ा**  
विशेष संवाददाता

## जब हिंदी फिल्मों में गूँजे संविधान को बचाने के डॉयलाग

चुनावी समर में फिल्मी डॉयलाग इन दिनों बेशक गायब से है, लेकिन लोगों के जहन में वो आज भी गूँजते हैं. एक ओर जहां सियासी मंच के बयान आपको अक्सर याद रह जाते होंगे तो वहीं आपने ऐसी फिल्में भी जरूर देखी होंगी, जिनमें सियासी दांव-पेंच और बयानों को बखूबी दर्शाया गया होगा, देखा जाए तो सियासत की वास्तविक दुनिया सिनेमा की स्क्रीन से कम फैंटेसी नहीं होती. परख, मेरे अपने, गॉडमदर, राजनीति, किस्सा कुर्सी का, क्रांतिवीर, प्रतिघात, विरासत जैसी अनेक फिल्में हैं जहां लोकतंत्र और संविधान का ज्ञान बखूबी दिया गया है. जहां एक तरफ इन फिल्मों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जबरदस्त मैसेज दिया गया है तो वहीं कुर्सी के लिए किए जाने वाले सियासी दांव-पेंचों को भी बखूबी दुनिया के सामने रखा गया है.

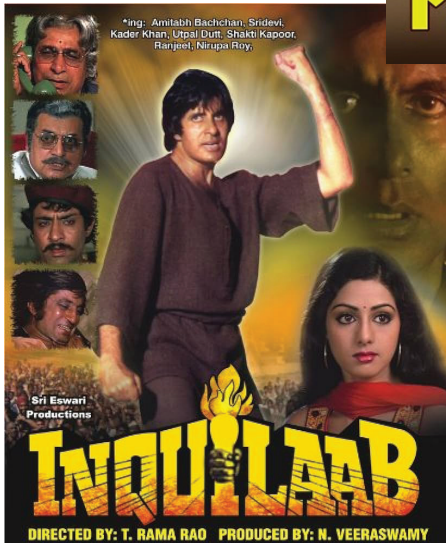
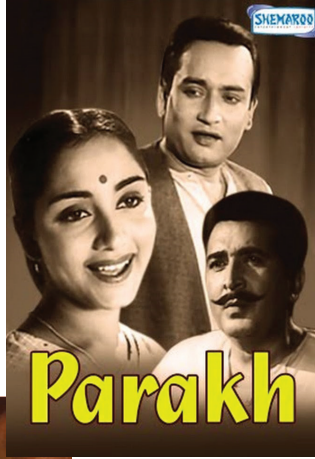
### ‘जवान’ के डॉयलॉग ने किया दिलों पर कब्जा

शाहरुख खान की फिल्म जवान के सबसे अहम हिस्से में कई बड़े सवाल छोड़ जाते हैं. उनका यह मोनोलॉग आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है. वो कहते हैं- जिस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके जरिए अपने नेता से सवाल करो. पांच घंटे चलने वाले मॉस्किटो ऑयल के लिए कितने सवाल करते हो. लेकिन पांच साल तक चलने वाली अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं पूछते. इसीलिए मेरी डिमांड है ये उंगलीsss. घर-पैसा-जात-पात-धर्म-संप्रदाय के लिए जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछोsss. उससे पूछो... अगले पांच साल तक तुम क्या करोगे. पांच साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे.



## ‘काका’ की फिल्म के डॉयलॉग ने छोड़ी छाप

साल 1984 में जब संसदीय राजनीति का खुरदुरा चित्रण करने वाली अमिताभ बच्चन की इंकलाब जैसी फिल्म आई थी, उसी साल राजेश खन्ना की आज का MLA रामअवतार फिल्म भी आई थी. उसमें राजेश खन्ना का एक लंबा संबोधन था जैसे कि जवान में शाहरुख खान का. राजेश खन्ना ने वोटिंग के महत्व को समझाया था. राजेश खन्ना ने बोलना शुरू किया था- हमारे देश में समाजवाद कहां है... अवसरवाद है, जातपातवाद है. समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे. ये जो वोट है न... कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए. ये वोट तुम्हारे देश, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश की उन्नति की पर्ची है. ये तो दोधारी तलवार है. दोनों तरफ से काटती है. ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल, गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश. राजेश खन्ना आगे कहते हैं- अरे भाई, हम तो आपसे एक सवाल पूछते हैं. जब आप अपनी बहन या बिटिया की शादी के लिए अच्छा लड़का ढूंढते हैं अच्छा खानदान देखते हैं उसके गुण और अवगुण देखते हैं तब जाकर कन्या की शादी करते हैं. वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है न! अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए. कभी दोस्त को दे दिया कभी अपनी जात वाले को दे दिया. और कभी बेच दिया. अगर बेईमान लोग सरकार बनाएंगे तो सरकार बेईमान बनेगी ही. राजनीति में सब बेईमान नहीं- बहुत से लोग शरीफ और ईमानदार भी हैं. हम इस मंच से यही कहते हैं कि उन ईमानदार लोगों की जय जयकार करो. उन्हीं को वोट दो, उन्हीं की सरकार बनाओ और लोकतंत्र के हाथ मजबूत करो. ईमानदार लोगों को विधानसभा



और लोकसभा में भेजो- इसी में देश का कल्याण है.

## राजनीति विषय का चित्रण बहुत कम

आज का MLA रामअवतार, जवान या न्यूटन इस मायने में सबसे अलग फिल्में हैं कि यहां जनता को लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरूक किया जाता है. ऐसी जागरूकता के अंश हम अनुभव सिन्हा की फिल्में मुल्क और आर्टिकल 15 में भी देखते हैं लेकिन सिनेमा के पर्दे पर राजनीति जैसे विषय का सकारात्मक चित्रण बहुत कम ही हुआ है. मतदान की जागरूकता के नजीर तो और भी कम हैं. थोड़ा इतिहास में चलें तो सन् 1960 में रिलीज बिमल रॉय की फिल्म परख की याद आती है. देश को आजाद हुए महज 12-13 साल हुए थे लेकिन सत्ता की राजनीति इतनी दुर्दशाग्रस्त हो जाएगी, भला किसने सोचा था. आपातकाल से पहले गुलजार की मेरे अपने या फिर आपातकाल के साल में रिलीज आंधी ने भी संसदीय राजनीति, नेताओं के चरित्र और चुनाव में होने वाली धांधलियों का विद्रूप चित्रण किया है. मेरे अपने में श्याम (विनोद खन्ना) और छेनू (शत्रुघ्न सिन्हा) की लड़ाई केवल दो दलों की लड़ाई नहीं है बल्कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों के प्रति आक्रोश की ज्वाला है.

## ‘किरसा कुर्सी का’ तो बहुत कुछ बयां करता है

आपातकाल के समय प्रतिबंधित किरसा कुर्सी का तो अलग ही पॉलिटिक्स बयां करती है. सन् 80 का दशक आते-आते तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को हिंदी सिनेमा का प्रमुख विषय ही बना दिया गया. फलस्वरूप प्रतिघात, गॉडमदर जैसी फिल्में आती हैं जहां चुनाव के दौरान लोकतंत्र का चीरहरण होते दिखाया जाता है. आगे चलकर प्रकाश झा ने राजनीति, अपहरण, आरक्षण जैसी कई फिल्में बनाईं जहां सियासत के ऐसे चेहरे दिखाए गए जो आम दिनों में अक्सर हमारी आस-पास की दुनिया में पाए जाते हैं. इन फिल्मों में दिखाए गए इन किरदारों का भी मकसद साफ था- दर्शक लोकतंत्र के विलेन को पहचानें और अपने सबसे मजबूत औजार वोटिंग का सोच समझ कर प्रयोग करें.

## राजकुमार राव की ‘न्यूटन’ ने किया जागरूक

राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन को याद कीजिए. यह फिल्म 2017 में आई थी. इस फिल्म की कहानी नक्सलवाद प्रभावित इलाके की है, जहां लोगों में ईवीएम को लेकर तरह-तरह की धारणाएं हैं. लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते. लेकिन राजकुमार राव का किरदार नक्सल क्षेत्र में लोगों को लोकतंत्र में चुनाव और संविधान की अहमियत बताने के लिए अनोखा जागरूकता अभियान चलाता है.

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को गौतमबुद्ध नगर सीट पर पंद्रह प्रत्याशियों की किस्मत को मतदाताओं ने अपने मताधिकार से फैसला किया, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के जिला प्रशासन को प्रयासों को धक्का लगा। गौतमबुद्ध नगर में मतदान प्रतिशत महज 53.66 पर सिमट कर रहा गया। पिछले लोकसभा चुनाव के सापेक्ष यह 6.73 प्रतिशत कम रहा। 2019 के लोकसभा चुनावों में 60.39 प्रतिशत वोट पड़े थे।

### पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने किये वोट

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मतदान के प्रति अधिक उत्साह रहा। पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा के बीच हुए शांतिपूर्ण मतदान में कुछ जगह पर ईवीएम खराबी की शिकायत मिली। इससे मतदान प्रभावित हुआ। सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही मतदाताओं

का मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। आसमान में छाये बादलों ने भी मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को राहत दी। लेकिन सूरज की गर्मी बढ़ने के साथ ही मतदान केंद्र सूने होते गए। दोपहर में कईबूथों पर मतदाता नदारद थे। ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला चार जून को होगा। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच नोएडा फेज दो स्थित फूलमंडी में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया है।

### दिन ढलने के साथ गिरा मतदान प्रतिशत

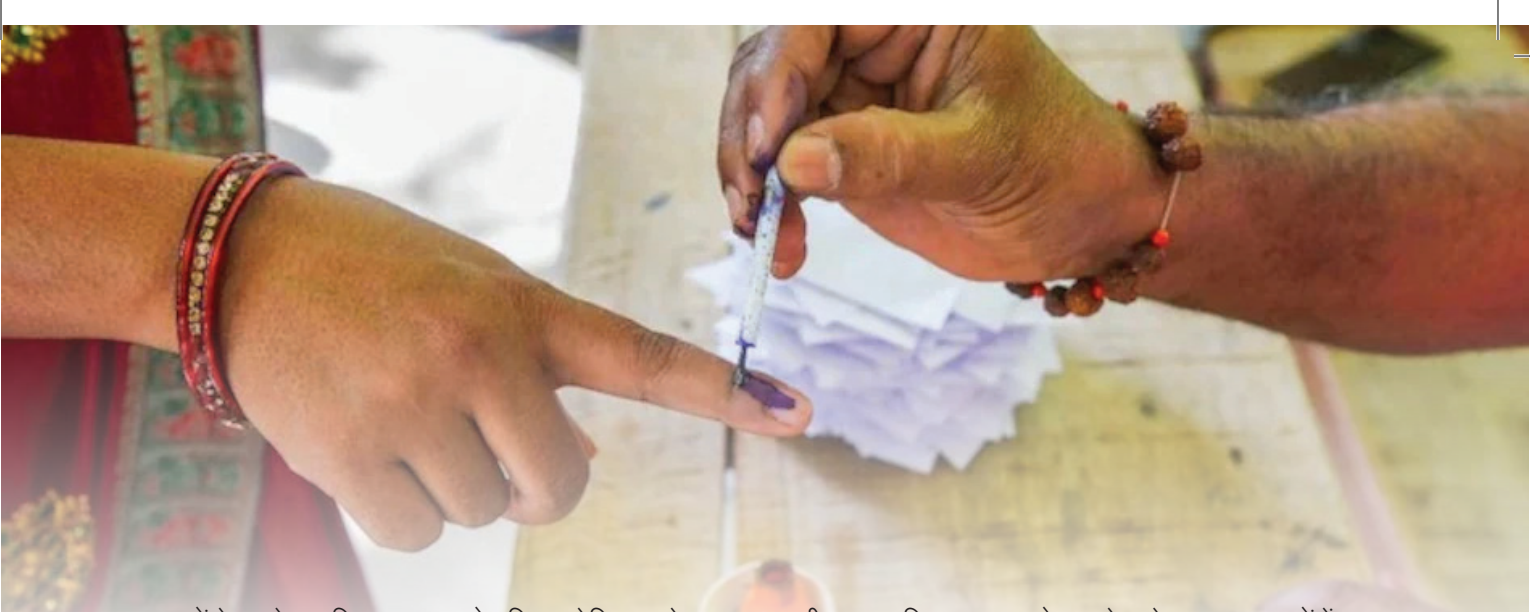
गौतमबुद्ध नगर में मतदान के लिए 1098 मतदान केंद्रों पर 2691 मतदेय स्थल बनाए गए थे। शहरी क्षेत्र में सुबह सात बजे से शुरू हुए मतदान में मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए मतदान किया। नोएडा व ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी। शुरुआती कुछ घंटों में गौतमबुद्ध नगर सीट पर 24.26 प्रतिशत

# मतदान प्रतिशत गिरने का मतलब क्या?



यूनस आलम,  
ब्यूरो चीफ





मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। लेकिन इसके बाद मतदान की गति लगातार धीमी होती गई। आखिरी एक घंटे में महज 0.80 प्रतिशत मतदान ही हुआ। कुछ बूथ पर व्हील चेयर की सुविधा न मिलने से दिव्यांगों को मतदान स्थल तक पहुंचने में परेशानी हुई। बुजुर्ग मतदाता स्वजन का सहारा लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे।

### प्रत्याशियों ने डाले वोट

भाजपा प्रत्याशी डॉ. महेश शर्मा ने नोएडा सेक्टर 15 ए में परिवार के साथ मतदान किया। राज्यसभा सदस्य और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र नागर ने ग्रेटर नोएडा में मतदान किया। गठबंधन प्रत्याशी डा. महेंद्र नागर ने मिल्क लच्छी और बसपा प्रत्याशी ने बुलंदशहर में अपना वोट डाला। निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा समेत प्रशासन के अधिकारी व प्रत्याशी दिन भी एक बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचकर मतदान की स्थिति की जानकारी लेते रहे। मतदान बूथ पर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध के कारण मतदाता परेशान हुए।

### प्रत्याशियों में भी निराशा

जैसे-जैसे सूरज की तपिश बढ़ी, मतदान बूथ से मतदाताओं की कतारें नदारद होगी गईं। दोपहर तक कई बूथ पर इक्का दुक्का मतदाता ही मतदान करने पहुंचते नजर आए। बिलासपुर के डा. राजेंद्र प्रसाद इंटर कालेज, किसान आदर्श इंटर कालेज में मतदान केंद्र सूने दिखे। बसपा सुप्रीमो मायावती के पैतृक गांव बादलपुर में भी मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखाई दिया। मतदाताओं की बेरुखी के कारण बूथ पर नियुक्त प्रत्याशियों के एजेंट भी निराश हुए। कुछ केंद्रों पर पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण मतदान पर असर पड़ा। मतदान की गति धीमी रही। नोएडा सेक्टर 12 के प्राथमिक पाठशाला की बूथ संख्या 93, सेक्टर 66 के मामूरा में बूथ संख्या 161 पर ईवीएम खराब होने पर उसे बदला गया। सेक्टर 82, सेक्टर 128, सेक्टर 27 समेत अन्य बूथ पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली। रबूपुरा के तिरथली गांव के प्राथमिक विद्यालय की बूथ संख्या 238 पर मतदाताओं को मतदान के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। नगला हुकुम सिंह के प्राथमिक विद्यालय में बने मतदान बूथ 265 पर भी मतदान की गति काफी धीमी रही। इस वजह से मतदाताओं की लंबी कतार लगी। दो जगहों पर ईवीएम को बदला गया।

पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले युवा मतदाताओं में खासा जोश रहा। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बढ़चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्र के बार सेल्फी प्वाइंट पर फोटो खिंचाकर पल को यादगार बनाया।

### सपा ने धीमी गति से मतदान कराने का लगाया आरोप

समाजवादी पार्टी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर नोएडा में बूथ संख्या 234 पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। इसके अलावा महिला मतदाताओं की पुलिस कर्मियों से चैकिंग का भी आरोप लगाया, हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक्स हैंडल से आरोप को खारिज कर दिया। सपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर ने कहा कि कुछ मतदानकर्मी दूसरी पार्टी का एजेंट बनकर काम किया। उन्होंने मिल्क लच्छी समेत कई गांव में धीमे मतदान कराने की शिकायत की।

### सूची में नाम नहीं होने पर कुछ मतदाता मायूस वापस लौटे

मतदान करने पहुंचे कई लोगों के नाम मतदाता सूची में न होने पर उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-36 स्थित उर्स लाइन कान्वेंट स्कूल के मतदान केंद्र पर पहुंची शिवानी चटर्जी का नाम मतदाता सूची में न होने पर उन्हें निराशा मिली। सेक्टर स्वर्ण नगरी के निवासी सुरेश पाल त्यागी भी अपना नाम मतदाता सूची में तलाशते रहे लेकिन निराशा हाथ लगी।

### जिला प्रशासन के प्रयासों पर फिरा पानी

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के जिला प्रशासन के प्रयासों पर पानी फिर गया। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं के खेतों में फसल काटने में व्यस्त रहने के कारण मतदान प्रतिशत पर सीधा असर पड़ा। मतदाता वोट डालने नहीं पहुंचे। वहीं मतदान के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाश का फायदा शहरी मतदाताओं ने उठाया। शुक्रवार के साथ शनिवार और रविवार का अवकाश होने के कारण अधिकतर शहरी मतदाता परिवार के साथ शहर से बाहर मौज मस्ती करने के लिए रवाना हो गए। इसके चलते मतदान प्रतिशत कम हो गया। गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत आने वाली नोएडा विधानसभा में सबसे कम 46.48 प्रतिशत और बुलंदशहर जिले के सिकंद्राबाद विधानसभा क्षेत्र मंक सबसे अधिक 60 प्रतिशत मतदान हुआ।

# विधानसभा क्षेत्र मतदान प्रतिशत



## इस तरह रही मतदान की गति

सुबह 11 बजे तक  
24.48 प्रतिशत

दोपहर एक बजे तक  
36.06 प्रतिशत

दोपहर तीन बजे तक  
44.01 प्रतिशत

शाम पांच बजे तक  
51.60 प्रतिशत

शाम छह बजे तक  
53.66 प्रतिशत





THE PLEASURE OF  
VARIETY ON YOUR PLATE

COUNT THE MEMORIES NOT  
THE CALORIES



More Information  
9910625795



More Information  
[www.thestreetviewrestro.com](http://www.thestreetviewrestro.com)



# What Are You Craving For ?

KURKURE MOMOS



NOODLES



FRENCH FRIES



FRIED RICE



More information  
9910625795



More information  
[www.thestreetviewrestro.com](http://www.thestreetviewrestro.com)



# दोनों चरणों में कम पड़े वोट



**साजिद अली**  
विशेष संवाददाता

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकसभा चुनाव साल 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुआ, जबकि दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को। पहले चरण में 64 फीसदी वोटिंग हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की लोकसभा सीटें शामिल रहीं। इन सीटों पर बने 2 लाख मतदान केंद्रों पर 16.63 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले हैं। अगर यूपी की बात करें तो दूसरे चरण में 54.83 फीसदी मतदान हुआ, जो कि पहले चरण की तुलना में 5.76 फीसदी कम वोटिंग हुई।

बढ़ती गर्मी का असर 26 अप्रैल को दूसरे चरण में यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर हुए मतदान पर दिखा। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद,

## यूपी में दूसरे चरण में हुए मतदान की तुलना करें तो साल 2019 लोकसभा चुनाव में...

सीट	2019	2024
अमरोहा	71.05	64.02
मेरठ	64.29	58.70
अलीगढ़	61.68	56.62
बागपत	64.68	55.93
बुलंदशहर	62.92	53.21
गौतमबुद्ध नगर	60.49	53.21
गाजियाबाद	55.89	49.65
मथुरा	61.08	49.29
<b>औसत</b>	<b>62.76</b>	<b>54.85</b>



गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर(अजा), अलीगढ़ और मथुरा में महज 54.83 फीसदी मतदान हुआ। ये पहले चरण की तुलना में करीब 5.76 फीसदी कम है। 19 अप्रैल को पहले चरण में प्रदेश में कुल 60.59 फीसदी मतदान हुआ था। वहीं 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर हुए मतदान से यह 7.93 फीसदी कम है। इस बार 64.02 फीसदी वोटिंग के साथ अमरोहा पहले स्थान पर रहा। मथुरा में सबसे कम 49.29 फीसदी वोट पड़े। सभी जिलों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।

### वोटिंग प्रतिशत गिरने का मतलब क्या?

दो चरण में मतदान के बाद 191 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुका है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों के लिए होने वाले मतदान तक लोकसभा चुनाव 2024 पूरे रंग में आ जाने के आसार हैं। हमेशा से कम मतदान को लेकर कहा जाता है कि वोटरो में सरकार के प्रति उदासीनता है। हालांकि भारत में चुनावों का इतिहास बताता है कि कम या ज्यादा मतदान के नतीजे मिले-जुले ही आते रहे हैं। इसे परिवर्तन या फिर यथा स्थिति के अनुमान के कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। जिसके चलते गिरते वोट प्रतिशत दोनों दलों के सामने बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

वैसे ये धारणा पहले से बनी है कि जहां-जहां मुस्लिम समुदाय की संख्या अधिक होती है, वहां बूथों पर वोट ज्यादा बरसता है और दूसरे समुदाय की अधिकता वाले बूथों पर मत के प्रति लापरवाह या उदासीन रहते हैं। इस बार इस धारणा पर चोट लगती दिखाई दे रही है। पहले चरण का मतदान बता

रहा है कि सभी सीटों पर वोटरो में बूथों पर जाने से परहेज किया है। वहां भी जहां पिछले दो चुनावों से 70 प्रतिशत से ज्यादा वोट पड़ रहे थे, इस बार पांच से दस प्रतिशत तक कम वोट पड़े हैं। 2019 और 2014 से तुलना करें तो यूपी में पहले चरण की आठ सीटों में से पांच पर कम वोट पड़े। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर एवं नगीना के वोटरो में उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा क्यों हुआ? मतदान में गिरावट से पार्टियों की हार-जीत पर भी असर पड़ सकता है क्या?

भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों के विरुद्ध आगे बढ़कर वोट करने वाले मुस्लिम समुदाय में दो वजहों से उदासीनता आई है। पहला, आबादी के अनुरूप सियासत में हिस्सेदारी देने का भरोसा दिलाने वाले दलों ने उनके साथ नाइंसाफी की है। टिकट वितरण में भेदभाव किया है।

बिहार में राजद ने अपने हिस्से की अनारक्षित कुल 20 सीटों में नौ टिकट उस बिरादरी को दे दिए, जिसकी संख्या राज्य में 14 प्रतिशत है, किंतु मुस्लिमों की आबादी 17.70 प्रतिशत रहते हुए भी उन्हें सिर्फ दो टिकट दिए।

अनदेखी के चलते उनमें निराशा का भाव है। दूसरा कारण है कि मुस्लिम वोटरो के जुनून में कमी आना है। भाजपा को हराने के लिए पिछले दो चुनावों में बढ़-चढ़कर वोट डालने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। उल्टे संसद में भागीदारी कम होती गई। ऐसे में मतदान के प्रति उत्साह कम हुआ है।





# चुनाव के समय गोल्ड और कैश लेकर चलने के नियम

लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की कोशिश रहती है। आचार संहिता लागू होते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो जाता है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इनकम टैक्स विभाग, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सभी एजेंसियां सतर्क हैं। चौराहों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। जिससे वोटर्स को लुभाने के लिए बड़ी मात्रा में कैश और शराब न ले जाया जा सके। उत्तर प्रदेश के लिए अलग-अलग जिलों में नकदी के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं। पकड़े गए पैसों को चुनाव आयोग कब्जे में लेकर बाद में सरकारी खजाने में जमा करा देता है। हालांकि आम नागरिकों के लिए अलग नियम हैं, बस इस समय कैश लेकर चलते समय ध्यान रखने की जरूरत है।

## कैश के साथ रखें ये डाक्युमेंट

आचार संहिता लागू होने के बाद आम नागरिक बिना किसी दस्तावेज के अपने साथ 49 हजार रुपये ले जा सकता है। लेकिन 49 हजार रुपये से अधिक कैश ले जाने पर हिसाब देना होगा। यदि हिसाब नहीं दे पाए तो मान लिया जाएगा, ये रकम चुनाव में इस्तेमाल के लिए ले जाई जा रही है और जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में अगर आप 49 हजार रुपये से अधिक पैसे अपने साथ लेकर कहीं जा रहे हैं तो किस बैंक या एटीएम से निकाला है, उसकी पर्ची रखें। इसके अलावा पैसों का सोर्स, पहचान पत्र के साथ पैसे कहां खर्च किया जाना है, ये डाक्युमेंट साथ होना चाहिए। इसलिए 50 हजार से अधिक कैश इस समय लेकर घर से निकल रहे हैं, तो पहले दस्तावेज चेक कर लें, नहीं



तो पैसे सरकारी खजाने में पहुंच जाएगा। इसके अलावा कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।

### 10 लाख से अधिक कैश ले जाने के लिए ये हैं नियम

अगर आप किसी जरूरी काम से 10 लाख रुपये से अधिक लेकर कहीं जा रहे हैं। अगर ये पैसे किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। अगर आप शादी या अस्पताल के लिए 10 लाख रुपये लेकर जा रहे हैं, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, जिसे दिखाने पर सर्विलांस टीम या पुलिस आपको ले जाने देगी लेकिन इनकम टैक्स विभाग को सूचना जरूर दे देगी।

### क्या चुनाव के बाद लौटा दिए जाते हैं पैसे?

आचार संहिता लागू के समय पैसे पकड़े जाने पर अगर कोई दस्तावेज न देने पर सर्विलांस और स्टैटिक्स टीम पैसे सीज कर लिए जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद और तब भी पर्याप्त सबूत देने के बाद ही लौटाए जाते हैं, लेकिन नकद 10 लाख से अधिक का है तो आयकर विभाग जांच करेगा।

### एक तोला सोना ही ले जा सकते हैं

चुनाव आयोग के मुताबिक आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक तोला सोना ही साथ लेकर चल सकता है। इसकी कीमत अधिकतम 50 हजार रुपए होनी चाहिए। अगर पास इससे ज्यादा गोल्ड मिलता है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं।

### कैश और गोल्ड बरामदगी के बाद क्या होता है?

आभूषण और महंगे गिफ्ट बरामद होने के बाद पहले इलेक्शन कमीशन पूछताछ करती है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करने के साथ पूछता करता है। पूछताछ और जांच में अगर पता चल जाता है कि कैश या गोल्ड मतदाताओं को लुभाने के लिए ले जा जाया रहा था तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद कोर्ट में केस चलता है, यदि कोर्ट में पैसे के लीगल सोर्स और चुनाव से कोई संबंध नहीं था तो, पैसे और आभूषण वापस कर दिए जाते हैं।



# सरकारी एजेंसियों की कारवाइ

दो चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गये हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही, सरकारी एजेंसियों के जांच का दायरा भी बढ़ जाता है। आचार संहिता लागू होने के साथ नियम के मुताबिक ही कैश, ज्वेलरी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकारी एजेंसी ने 1 मार्च से 21 अप्रैल तक 31648.92 लाख कीमत की शराब धातुएं और नकदी जब्त की हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान 21 अप्रैल को सबसे बड़ी कारवाइ देखने को मिली, जब मात्र एक दिन में 129.01 लाख रुपए की शराब और ड्रस पकड़े गए।

बात अगर गौतमबुद्ध नगर जिले की करें तो आबकारी विभाग दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक्शन मोड में नजर आया। यहां पर अवैध शराब की खेप को पकड़ने के लिए 7 मोबाइल वैन टीम का गठन किया गया था। इसमें दो टीमों को ईस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तैनात किया गया था, जो सिरसा कट और झुप्पा कट पर 24 घंटे वाहनों पर निगरानी रख रहे थे। इसके अलावा जिले से सटे राज्यों की सीमा पर भी आबकारी विभाग की तैनाती बढ़ाई गई थी। 16 मार्च से 25 अप्रैल तक आबकारी विभाग की चेकिंग के दौरान लगभग 10 हजार लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपये आंकी जा रही है।





# विश्व में 28 करोड़ लोगों को पड़े रोटी के लाले



संयुक्त राष्ट्र के 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस' की रिपोर्ट एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिसके मुताबिक 2023 में 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोग भूख से तड़पने को मजबूर हुए। इसमें सबसे अधिक युद्धग्रस्त गाजा में लोग शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र में खाद्य-कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि 2016 में वैश्विक रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत के मुकाबले भूख से तड़पने वालों की यह संख्या अब तक सर्वाधिक है। टोरेरो ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया है, जिसमें पांच देशों के 7,05,000 लोग पांचवे चरण में हैं, जिसे उच्च स्तर माना जाता है।

## 1 साल में 24 करोड़ पीड़ित बड़े

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी सूडान, बुर्किना फासो, सोमालिया और माली में हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं। अनुमान है कि गाजा में 11 लाख व दक्षिण सूडान में 79 हजार लोग जुलाई तक 5वें चरण में पहुंच सकते हैं। इसी के साथ उनके अकाल का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, मौसम की घटनाओं और आर्थिक झटकों के कारण गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वालों की संख्या में 2022 की तुलना में 24 करोड़ लोगों तक बढ़ गई है। 2022 में सिर्फ 4 करोड़ लोग भूख से तड़प रहे थे।

## खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या 282 मिलियन

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मुताबिक, पिछले साल गाजा में 600,000 लोगों सहित लगभग 700,000 लोग भुखमरी की कगार पर थे, यह आंकड़ा तब से युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में 1.1 मिलियन तक बढ़ गया है। 2016 से लेकर अब तक खाद्य-असुरक्षित लोगों की संख्या 108 मिलियन से बढ़कर 282 मिलियन हो गई है। अफगानिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, नाइजीरिया, सीरिया और यमन में लंबे समय से प्रमुख खाद्य संकट जारी है।

## संघर्ष-असुरक्षा भूख का मुख्य कारण

रिपोर्ट के अनुसार, संघर्ष या असुरक्षा की स्थितियां 20 देशों या क्षेत्रों में तीव्र भूख का मुख्य कारण बन गई हैं, जहां 135 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ या सूखा जैसी जलवायु घटनाएं 18 देशों में 72 मिलियन लोगों के लिए तीव्र खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण थीं, जबकि आर्थिक झटके ने 21 देशों में 75 मिलियन लोगों को इस स्थिति में धकेल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, "वैश्विक खाद्य कीमतों में गिरावट का असर कम आय वाले, आयात पर निर्भर देशों तक नहीं पहुंचा। साथ ही, उच्च ऋण स्तर ने "उच्च कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के विकल्पों को सीमित कर दिया। रिपोर्ट में सकारात्मक बात यह है कि 2023 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और यूक्रेन सहित 17 देशों की स्थिति में सुधार हुआ है।



ऋषभकांत छाबड़ा  
विशेष संवाददाता

# स्क्रेप माफिया के काले साम्राज्य का “द एंड” ?

थाईलैंड से गिरफ्तार कर भारत लाए गए स्क्रेप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा ने नोएडा पुलिस की पूछताछ के दौरान कई बड़े राज उगले हैं। स्क्रेप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड से पुलिस ने करीब आठ घंटे पूछताछ की। सूत्रों की माने तो दोनों से पूछताछ में कई सफेदपोश नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों के नाम सामने आए हैं। जांच और पूछताछ के बाद समय के साथ कई नए खुलासे भी सामने आने की पूरी संभावना है। रवि काना स्थानीय मीडिया के साथ नेशनल मीडिया में भी छाया हुआ है। तो आइये आप और हम भी जान लेते हैं कि कौन है रवि काना-

## कैसे बना स्क्रेप और सरिया तस्करी का बादशाह?

रवि काना ग्रेटर नोएडा के दादपुर निवासी हरेंद्र प्रधान उर्फ हरेंद्र नागर का छोटा भाई है। पुलिस और क्षेत्र के जानकारों की मानें तो एक दशक पहले तक रवि काना छोटे मोटे काम किया करता था। 8 फरवरी 2015 में वेस्ट यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी ने हरेंद्र प्रधान की हत्या करा दी थी। इस हत्याकांड ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया था। हत्याकांड के बाद रवि काना ने अपनी जान को खतरा बताते हुए यूपी पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। इसके बाद उसे और हरेंद्र प्रधान की पत्नी व

दूसरे भाई राजकुमार को यूपी पुलिस की सुरक्षा मिल गई। इसी सुरक्षा का फायदा उठाकर रवि काना स्क्रेप और सरिया तस्करी का बादशाह बन गया। गैंगस्टर हरेंद्र प्रधान की हत्या के बाद रवि काना पूरी तरह जुर्म की राह पर आ गया। उसने लोगों में भय पैदा करके जबरन ट्रकों से सरिया उतरवा कर कंपनियों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच वह नामी बदमाश अनिल दुजाना के संपर्क में आया और उसका दाहिना हाथ बन गया। बाद में जब अनिल दुजाना पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो अपराध की दुनिया में वह तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। जिसके बाद ग्रेटर नोएडा में काना पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, काना को रवींद्र नागर के नाम से भी जाना जाता है।

## रवि नागर का आपराधिक इतिहास

गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ मुकदमों की फेहरिस्त लंबी है, जिस माफिया रवि काना को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस को ऐड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा, उसे लगभग 6 महीने पहले तक शायद ही कोई जानता हो। उसका स्क्रेप और सरिया चोरी का गोरखधंधा आराम से फलफूल रहा था, लेकिन बीते साल 30 दिसंबर को थाना सेक्टर 39 में एक युवती ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता के मुताबिक रवि काना समेत 5 लोगों ने उसके साथ लगभग 6 महीने पहले गैंगरेप रेप की घटना को अंजाम दिया फिर वीडियो बनाकर उसे धमकाते रहे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले वो नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रवि काना के साथी राजकुमार और मेहमी से हुई। दोनों ने कहा कि उसे नौकरी रवि





सर दे सकते हैं, जिसके बाद दोनों पीड़िता को गार्डन गलेरिया मॉल के पार्किंग में ले गए और रवि काना एवं उसके साथी आजाद और विकास से मुलाकात करवाई। इसी दौरान बंदूक दिखाकर उसके साथ गैंगरेप किया और वीडियो भी बनाया। इस घटना के बाद से ही रवि काना की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कसर कस ली है।

#### **स्क्रेप कारोबार से बना करोड़ों की संपत्ति का मालिक**

देश की राजधानी दिल्ली में रवि काना की चार कोठियां हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 400 करोड़ रुपए है। अभी तक पुलिस उसकी दो फैक्ट्रियों पर छापा मारकर लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को सील कर चुकी है। फरवरी 2024 में 80 करोड़ रुपए कीमत के उसके तीन प्लॉट अटैच किए गए। इनमें से एक प्लॉट उसके नाम पर बुलंदशहर और

बाकी दो नोएडा में हैं। इनके अलावा पुलिस ने रवि काना की दो फैक्ट्रियों से ही 12 गाड़ियां सील की। जब्त की गई गाड़ियां में 11 ट्रक और एक कार शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने पांच बैंक खातों को सीज किया। इन खातों में करीब 4 करोड़ रुपए जमा थे। ग्रेटर नोएडा के इस गैंगस्टर के पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति भी थी। पुलिस के डंडे से उसकी बेनामी संपत्ति भी नहीं बच पाई। ग्रेटर नोएडा में रवि काना के सहयोगियों के नाम पर खरीदे गए दो प्लॉट पुलिस ने हाल ही में सील किए हैं। इन दोनों प्लॉट की कीमत करीब 33 करोड़ 95 लाख रुपए बताई जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में रवि काना के सहयोगी राज कुमार के नाम से एक फैक्ट्री है- एस्कॉन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पुलिस ने इस कंपनी से जुड़े बैंक खाते को भी सीज करा दिया है।

#### **इनके खिलाफ दर्ज है गैंगस्टर एक्ट का केस**

गैंगस्टर रवि काना की सलतनत की बात करें तो इनके 16 गैंग मेंबरों को पुलिस पहले ही अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। रवि की गैंग में गैंग लीड रवि काना, राजकुमार नागर, तरुन छोकर, अमन, विशाल, अवध उर्फ बिहारी उर्फ अमर सिंह, महकी नागर उर्फ महकार, अनिल, विक्की, अफसार, राशद अली, आजाद नागर, प्रहलाद, विकास नागर, काजल झा और रवि की पत्नी मधु को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। रवि और उसकी गर्लफ्रेंड काजल लंबे समय से फरार चल रही थी, जिसे थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया। माफिया रवि काना गैंग के पांच सदस्यों को अब तक जमानत भी मिल चुकी है। इसमें उसकी पत्नी मधु नागर का नाम भी शामिल है।





# UPSC फ्रैक करने का मूल मंत्र

कहते हैं कि दिल में जुनून और कुछ कर गुजरने की चाह हो तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल करने वाली वरदाह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 9 साल पहले अपने पिता को खो चुकी वरदाह ने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी मां की झोली में सारी दुनिया की खुशियां समेट कर डाल दीं। दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाली 24 साल की वरदाह खान ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी। वरदाह ने अपने दूसरे प्रयास में ही वरदाह खान ने ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की है। वरदाह अपनी पढ़ाई और सफलता का श्रेय अपनी मां को और अपने स्कूल के दोस्तों को देती है।

## दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट

माता-पिता की इकलौती बच्ची वरदाह खान ने बताया कि उन्होंने प्रतिदिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान उनके परिवारजनों और दोस्तों का भी काफी सहयोग रहा, जो उन्हें समय-समय पर मोटिवेट करते रहे। वरदाह खान ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा प्रयागराज से ही की है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। कुछ महीने कॉर्पोरेट जगत में काम करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया।

## 9 साल पहले हुआ वरदाह के वालिद का निधन

मूलरूप से प्रयागराज निवासी वरदाह खान नोएडा के सेक्टर 82 में

अपने रिश्तेदारों के घर रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थीं। नौ साल पहले उनके वालिद का निधन हो गया था। अपने पहले प्रयास में वह प्री परीक्षा भी नहीं निकाल पाई थीं। दूसरी कोशिश में वरदाह ने 18वीं रैंक लेकर हासिल कर ली। वरदाह खान ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर यूपीएससी की तैयारी की है। उनकी प्राथमिकता फॉरेन सर्विसेज है क्योंकि वह ग्लोबल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। ट्रेनिंग प्राप्त कर वह ऐसे काम करेंगे जिससे भारत देश की छवि विश्व में और ज्यादा चमक सके।

## 2021 से शुरू हुई यूपीएससी की तैयारी

वरदाह की मानें तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी तैयारी 2021 में शुरू हुई थी। 2021 में मैंने अपनी जॉब से इस्तीफा दिया था और तभी मैंने ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की थी। मैंने एक पूरे साल तैयारी की और 2022 में पहला अटेम्प्ट दिया तब मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला इसके अलावा वो मेरे लिए एक सबक भी था और एक मौका भी था कि जो मेरी आधी-अधूरी तैयारी थी मेन्स की तो वो मैं और बेहतर कर सकूँ और 2023 के लिए 2022 के एग्जाम ने मुझे एक मौका दिया। मेरा

**सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर  
यूपीएससी की तैयारी की पहले प्री निकाला, फिर  
मैस और इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर हासिल कर  
ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की है**





रिजल्ट उम्मीद से बेहतर रहा है। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी जब तैयारी करता है तो उसे यही उम्मीद होता है कि हमारा नाम आ जाए। लेकिन टॉप 20 में रैंक लाने के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था . तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए रिजल्ट उम्मीद से बेहतर है.

### **सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर यूपीएससी की तैयारी की**

वरदाह खान ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर यूपीएससी की तैयारी की पहले प्री निकाला, फिर मेंस और इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर हासिल कर ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की है। वरदाह खान का कहना है कि उनकी प्राथमिकता फॉरेन सर्विसेज में है। ट्रेनिंग प्राप्त कर वह ऐसे काम करेंगे जिससे भारत देश की छवि विश्व में और ज्यादा चमक सके। उन्होंने 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के दौरान उनके परिवार जनों और दोस्तों का भी काफी सहयोग रहा। जो उन्हें समय-समय पर मोटिवेट करते रहे। आपको बता दें कि मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली वरदाह खान ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा प्रयागराज से ही की। वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। कुछ महीने कॉर्पोरेट में काम करने के बाद सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया और अपने दूसरे ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल कर ली।

### **तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती होता है कॉम्पिटिशन**

इस एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है तो वो देख के भी हम डर जाते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं। दूसरा हम पूरी तरह से आइसोलेटेड होते हैं हमें सोशल मीडिया से भी दूरी बनानी पड़ती है। तो ये रास्ता एक समय के बाद काफी मुश्किल लगने लगता है। खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ऐसे समय में हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो पुराने रैंक होल्डर्स हैं। पुराने रैंक होल्डर्स रोल मॉडल की तरह हैं। तो उन्होंने भी बहुत सारी एक्टिविटी बताई हैं कि कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं अपने आप को छोटे टारगेट में, दूसरी चीजों के लिए भी समय निकाल सकते हैं।

### **परिवार की ओर से मिला पूरा सहयोग- वरदाह**

वरदाह ने बताया कि मुझे परिवार की ओर से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा. मैंने घर पर रहकर ही बड़े आराम से तैयारी

की. मैं इस दौरान घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी लेकिन किसी भी तरह का घरवालों की ओर से दबाव नहीं था उन्होंने मुझे काफी टाइम दिया अपनी स्पेस दी तैयारी करने की। जहां तक बात है मेरी मां की तो उन्होंने मुझे काफी इनकरेज किया कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बाकी चीजों का हम खयाल रख लेंगे।

### **यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए वरदाह का खास संदेश**

यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए वरदाह ने को दो संदेश दिए। पहला तो खुद पर बहुत भरोसा होना चाहिए क्योंकि अगर हम खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो कोई और भी हमारी काबिलियत पर विश्वास नहीं करेगा। दूसरा ये कि अपनी तैयारी को लेकर काफी ईमानदार रहना चाहिए क्योंकि अगर हमें कोई टॉपिक काफी अच्छे से समझ आ गया या मॉक टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर आ गए तो हम काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या पढ़ाई को लेकर केयर लेस हो जाते हैं.

### **माइंड चेंज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर**

वरदाह का कहना है कि सोशल मीडिया के गुण भी हैं और अवगुण भी हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया की रील कल्चर है इसमें काफी समय बर्बाद होता है. सोशल मीडिया पर पुराने रैंक होल्डर्स अपनी स्ट्रैटजी, रिसोर्सेस शेयर करते हैं तो उससे हमें वो हेल्प मिल सकती है. इसके अलावा करेंट अफेयर्स जैसे तो हम पढ़ते ही हैं स्टडी मटेरियल में लेकिन सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि कहां क्या हो रहा जो कि अवेयरनेस के लिए काफी अच्छा है और दूसरा जब हमारा पूरा दिन बीतता है पढ़ाई में तो जाहिर सी बात है 8-9 घंटे के बाद माइंड चेंज करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर है लेकिन हमें इसका समय निर्धारित करना चाहिए

इंटरव्यू के समय दो-तीन सिविल सर्वेंट्स ने काफी मुझे मोटिवेट किया वरदाह ने बताया कि इंटरव्यू की स्टेज में दो-तीन सिविल सर्वेंट्स ने काफी मुझे मोटिवेट किया जिनमें पिछले साल के मोईन अहमद, आयशा फातिमा और प्रेक्षा अग्रवाल से भी मेरी बात हुई थी तो इंटरव्यू के समय मुझे इनसे काफी हेल्प मिली थी.





प्रोफेसर (डॉ.) शैलेश मिश्रा  
(CE, FIETE, FISLE)  
वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद्

---

# “मृदा प्रदूषण”





प्रदूषण सिर्फ आकाश या वायु तक ही सीमित नहीं है; जिस मिट्टी पर हमारा भोजन उगता है वह भी प्रभावित हो रही है, जिसका सीधा परिणाम हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के माध्यम से हो रहा है। हमारे पैरों के नीचे क्या है उस पर ध्यान देना और इस मुद्दे के समाधान के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। इस बार हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में, जो की प्रदूषण का सबसे उपेक्षित प्रकार है।

मृदा प्रदूषण एक छिपी हुई समस्या है जो सतह पर प्रदूषकों की उच्च सांद्रता के कारण होती है, जिससे भूमि जैव विविधता को नुकसान होता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है, खासकर खाद्य प्रदूषण के माध्यम से।

डॉ शैलेश, मिश्रा मृदा प्रदूषण को एक वैश्विक खतरे के रूप में उजागर करते हैं: भारत में अधिकांश राज्य मृदा निम्नीकरण से प्रभावित हैं। सबसे खराब स्थिति पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में गंभीर है, जहां की एक तिहाई मिट्टी पहले से ही गिरावट से प्रभावित है।

स्टॉक ब्रीडिंग और सघन खेती जैसी गतिविधियों में रसायनों, कीटनाशकों, उर्वरकों, भारी धातुओं और अन्य पदार्थों का उपयोग मिट्टी प्रदूषण में योगदान देता है।

मृदा प्रदूषण से मुक्ति धीमी है, अनुमान है कि केवल कुछ सेंटीमीटर कृषि योग्य मिट्टी बनाने में 1,000 साल या इससे अधिक लग सकते हैं।

### मृदा प्रदूषण के कारण एवं प्रकार

1. मृदा प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है। मिट्टी के क्षरण के कुछ प्रमुख कारणों में कटाव, कार्बनिक कार्बन की हानि, नमक की मात्रा में वृद्धि, संघनन, अम्लीकरण और रासायनिक प्रदूषण शामिल हैं। ये घटनाएं मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट में योगदान करती हैं और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती हैं।

2. डॉ शैलेश मृदा प्रदूषण को दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: विशिष्ट प्रदूषण और व्यापक प्रदूषण। विशिष्ट प्रदूषण से तात्पर्य उस प्रदूषण से है जो छोटे क्षेत्रों में होता है और जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार का प्रदूषण अक्सर शहरों, पुराने कारखाने स्थलों, सड़कों के आसपास, अवैध डंपों और सीवेज उपचार स्टेशनों में पाया जाता है। दूसरी ओर, व्यापक प्रदूषण व्यापक क्षेत्रों को कवर करता है और इसके कई कारण हैं जिनका पता लगाना मुश्किल है। इसमें हवा, जमीन और जल प्रणालियों के माध्यम से प्रदूषकों का प्रसार शामिल है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है।





**भूमि उपयोग  
परिवर्तन और भूमि  
क्षरण के कारण  
69 गीगाटन CO2  
का अनुमानित  
उत्सर्जन होगा। यह  
चौंका देने वाला  
आंकड़ा वर्तमान  
वार्षिक ग्रीनहाउस  
गैस उत्सर्जन का  
लगभग 17% है**

3. मानवीय गतिविधियाँ मृदा प्रदूषण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें औद्योगिक गतिविधियाँ, खनन कार्य, सैन्य गतिविधियाँ, अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन (तकनीकी अपशिष्ट सहित), अपशिष्ट जल प्रबंधन, कृषि पद्धतियाँ, पशुधन प्रजनन और शहरी और परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल हैं। ये गतिविधियाँ मिट्टी में विभिन्न प्रदूषकों को शामिल करती हैं, जिससे इसका क्षरण होता है और पारिस्थितिक तंत्र और मानव कल्याण के लिए गंभीर खतरे पैदा होते हैं।

#### **मृदा प्रदूषण के परिणाम**

1. मृदा प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम होता है, क्योंकि जहरीले पदार्थ पृथ्वी की सतह को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारी भलाई पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये प्रदूषक न केवल भोजन, पानी और हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं।

#### **स्वास्थ्य को नुकसान**

2. मृदा प्रदूषण का एक प्रमुख प्रभाव मानव स्वास्थ्य को होने वाली क्षति है। जब विषाक्त पदार्थ दूषित मिट्टी के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, तो उनके परिणामस्वरूप विभिन्न बीमारियाँ और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण में एंटीबायोटिक दवाओं की मौजूदगी दवा-प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में योगदान करती है, जिससे बीमारियों का उपचार और भी जटिल हो जाता है।

#### **खराब फसल**

1. मृदा प्रदूषण एजेंटों के हानिकारक प्रभावों के कारण वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में है, जिससे मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में फसल खराब हो जाती है। ये एजेंट कृषि उत्पादकता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार कम हो जाती है और खाद्य उत्पादन में समझौता हो जाता है।

#### **जलवायु परिवर्तन**

2. जलवायु परिवर्तन के चिंताजनक मुद्दे के 2015 से 2050 तक गंभीर परिणाम होने का अनुमान है, जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तन और भूमि क्षरण के कारण 69 गीगाटन CO2 का अनुमानित उत्सर्जन होगा। यह चौंका देने वाला आंकड़ा वर्तमान वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 17% है, जो पहले से ही गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ा रहा है।

#### **जल एवं वायु प्रदूषण**

3. मृदा क्षरण से न केवल कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है, बल्कि हवा और पानी की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खासकर विकासशील देशों में। मिट्टी के क्षरण से वायु और जल संसाधनों का प्रदूषण होता है, जिससे मानव और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा होता है। यह पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में इन देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देता है।



### जनसंख्या विस्थापन

4. अनुमान है कि मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभावों के परिणामस्वरूप 2050 तक महत्वपूर्ण जनसंख्या विस्थापन होगा। अनुमान है कि इन पर्यावरणीय कारकों के कारण उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण 50 से 700 मिलियन लोग प्रवास करने के लिए मजबूर होंगे। लोगों के इस सामूहिक विस्थापन के गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होंगे, जो जलवायु परिवर्तन और मिट्टी के क्षरण से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों को और बढ़ा देंगे।

### प्रजातियों का लुप्त होना

1. जैव विविधता में गिरावट, जिसे प्रजातियों के विलुप्त होने के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर मुद्दा है जो मिट्टी के प्रदूषण से और भी गंभीर हो गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार, इस पर्यावरणीय समस्या के कारण वन्यजीवों की आबादी में उल्लेखनीय कमी आई है, 1970 और 2018 के बीच 69% की आश्चर्यजनक गिरावट आई है।

### मरुस्थलीकरण

2. एक और गंभीर चिंता का विषय मरुस्थलीकरण है, जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा करता है। 2050 तक, ये क्षेत्र वैश्विक आबादी के 45% का घर हो सकते हैं, जो इस मुद्दे को संबोधित करने की तात्कालिकता को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, पिछली तीन शताब्दियों में दुनिया के आर्द्रभूमि क्षेत्रों में 87% की कमी आई है, जिससे संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर और जोर दिया गया है।

### आर्थिक प्रभाव

3. मृदा क्षरण के आर्थिक परिणाम पर्याप्त हैं, वैश्विक आर्थिक नुकसान दुनिया के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधे से अधिक होने

का अनुमान है। यह मृदा प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के महत्व को रेखांकित करता है।

### मृदा प्रदूषण कम करने के उपाय

1. मृदा प्रदूषण को संबोधित करने के लिए सरकारों, संस्थानों, समुदायों और व्यक्तियों सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है।

2. मृदा प्रदूषण को कम करने के कुछ प्रभावी समाधानों में टिकाऊ भोजन का उपभोग करना, बैटरियों को ठीक से रीसाइक्लिंग करना, घर का बना खाद बनाना और निर्दिष्ट स्थानों पर दवाओं का निपटान करना शामिल है।

3. मृदा स्वास्थ्य पर प्रभाव को कम करने के लिए उद्योगों, कृषि और पशुधन खेती में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है।

4. शहरी और परिवहन योजना को बढ़ाना, साथ ही उचित अपशिष्ट जल उपचार को लागू करना भी मिट्टी प्रदूषण को कम करने में योगदान दे सकता है।

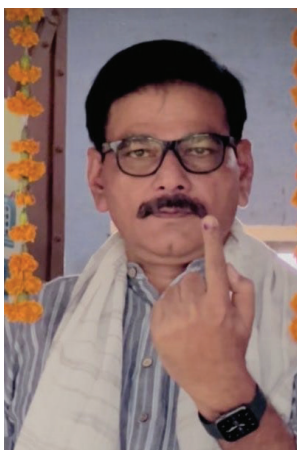
5. खनन कचरे का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना, परिटृश्यों को बहाल करना और ऊपरी मिट्टी को संरक्षित करना मिट्टी के क्षरण से निपटने के लिए आवश्यक कदम हैं।

6. इसके अलावा, स्थायी भूमि और मिट्टी प्रबंधन पहल में स्थानीय समुदायों और स्वदेशी समूहों को शामिल करने से मिट्टी प्रदूषण को संबोधित करने के लिए अधिक प्रभावी और समावेशी समाधान प्राप्त हो सकते हैं।





# लोकसभा महापर्व





# NOW NOIDA

अपडेट

सत्य से साक्षात्कार



## पत्रिका सदस्यता प्रपत्र

भारत के व्यक्तियों के लिए वार्षिक सदस्यता: ₹440

भारत के बाहर और कॉर्पोरेट दरें: ₹2,000

Name .....

Address.....

.....

.....

.....

Postcode.....

Telephone.....

Email.....

कृपया चेक या पोस्टल ऑर्डर करें

MBI Digital Private Limited को देया

# FASHION COLLECTION

SPECIAL OFFER

UPTO  
**20%**  
OFF

SHOP NOW

